



विधानसभा में भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित

■ मकान मालिक और किरायेदारों को मिलेगा बेहतर कानूनी संरक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। यह संशोधन राज्य में भवन स्वामी एवं किरायेदार के मध्य संबंधों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विधेयक बदलती सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं तथा भारत सरकार द्वारा सुझाए गए आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 के अनुरूप राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भौगोलिकसंदर्भ

लागू होगा किरायेदारी अनुबंध

संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किरायेदारी अनुबंध केवल मूल पक्षकारों तक सीमित न रहकर, उनकी मृत्यु अथवा अन्य परिस्थितियों में उनके विधिक हित-उत्तराधिकारियों पर भी लागू रहेगा। इससे अनावश्यक विवादों में



कमी आएगी तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी होगी।

कानूनी मान्यता

वर्तमान समय में अनेक भवन स्वामी अपनी संपत्तियों का प्रबंधन संपत्ति प्रबंधकों के माध्यम से करते हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए संशोधन में पहली बार संपत्ति प्रबंधक की विधिक परिभाषा, उसके अधिकार, दायित्व तथा दुरुपयोग की स्थिति में कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे भवन स्वामी एवं किरायेदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे तथा संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी।

नई व्यवस्था

संशोधन में ऐसी स्थिति के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है, जब भवन स्वामी किसी कारणवश किराया

स्वीकार नहीं करता। अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किराया जमा करने का प्रावधान रहेगा, जिससे किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और अनावश्यक विवादों से बचा जा सकेगा।विधेयक में भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की कार्यवाही को अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अनावश्यक स्थगनों पर रोक लगाने, अधिकतम तीन स्थानों की सीमा निर्धारित करने तथा यथासंभव 60 दिनों के भीतर मामलों के निराकरण का प्रयास करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अधिकरण को सिविल न्यायालय के समान समन जारी करने सहित आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।राज्य सरकार का मानना है कि यह संशोधन राज्य में किरायेदारी व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाएगा। इससे भवन स्वामियों का अपनी संपत्तियों को किराये पर उपलब्ध कराने के प्रति विश्वास बढ़ेगा, किरायेदारों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण होगा तथा आवासीय किराया बाजार को भी नई गति मिलेगी।

नकटी गांव में विधायक कॉलोनी नहीं बनेगी? विधानसभा में जमकर बहस

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को नकटी गाँव में बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा गुंजा. पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हुई. मुद्दे पर विपक्ष के स्थगन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे आसंदों ने अग्रह्य किया. आसंदों ने विपक्ष को पटल में पत्र रखने की भी अनुमति नहीं दी. इस पर विपक्ष ने गर्भगृह में जाकर की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ स्वमेव निलंबित हुए.

विधानसभा में आज की कार्यवाही के दौरान नकटी में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया. नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महेत ने कहा, नकटी गांव में जिन 85 घरों को तोड़ा गया, उनके से कई घर पीएम आवास से बने थे. पक्की बिजली, पानी की सुविधा थी. उन्हें जो वैकल्पिक घर दिया जा रहा है, वह बहुत छोटा है. कांग्रेस विधायकों ने कहा, उजाड़ने से पहले पुर्नवास की व्यवस्था होनी चाहिए. सांसद के आश्वासन के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई निंदनीय है. लखेश्वर बघेल ने कहा, विधायक कॉलोनी के लिए गरीबों के मकान तोड़ा जाना उचित नहीं है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा, नकटी में विधायक कॉलोनी निर्माण को लेकर यदि दस्तावेज है, तो उसे सदन की पटल पर रखा जाना चाहिए.नकटी गांव की चर्चा पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सदन में स्पष्ट किया कि पूर्णतः वैधानिक कार्रवाई है. अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अतिरिक्त तहसीलदार ने की. अवैध कब्जे पाए जाने पर उसे हटाने का आदेश 2025 में पारित किया गया. उसके बाद 28 जून को बेदखली की कार्रवाई की गई. मंत्री ने बताया कि अतिक्रमण कब्जाधारियों को हटाने से पहले उन्हें अपने सामान हटाने का समय दिया गया. प्रशासन की ओर से सेक्टर 30 , नवा रायपुर में प्रभावितों को फ्लैट दिया गया. अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास भी किया गया है।

सदन में उठा सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा



विधायक सुनील सोनी ने कहा - रायपुर के चारों दिशाओं में हो फायर स्टेशन, मंत्री विजय शर्मा बोले- जल्द खरीदी जाएगी नई दमकल गाड़िया



छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने राजधानी में फायर स्टेशन का मामला उठाया। उन्होंने कहा, रायपुर में 9 लाख की आबादी में चारों दिशाओं में फायर स्टेशन होनी चाहिए। कब तक इसका भूमिपूजन कराएंगे ? नेशनल एडवाईजरी के मुताबिक 2 लाख जनसंख्या में एक फायर स्टेशन होना चाहिए।

मंत्री विजय शर्मा ने कहा, एक फायर स्टेशन टिकरापारा में संचालित है। नगर निगम द्वारा एक संचालित है और एक फायर स्टेशन नवा रायपुर में इस तरह कुल 3 फायर स्टेशन मौजूद हैं। उन्होंने कहा, अभी रायपुर में 22 गाड़ियों के साथ कार्य चल रहा है। अप्रैल-मई महीने में राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन विभाग से नई गाड़ियों की खरीदी होनी है।

विधायक सुनील सोनी ने कहा, एक महीने में ही 6 से ज्यादा आगजनी की घटना हुई है, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कम संसाधन में काम हो रहा है। कई संस्थाओं की गंभीर लापरवाही पाई गई है। बहुत जल्द इस पर बैठकर चर्चा कर कार्य किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में सेमीकॉन 2.0 मिशन और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को कैबिनेट की मंजूरी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीई) की बैठक में देश की विनिर्माण क्षमता, बुनियादी ढांचे, कृषि, परिवहन और समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक

विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इतिहास कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) को 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहने वाली इस योजना के तहत भारत में मोबाइल फोन निर्माण पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर प्रमुख कंपोनेंट्स की खरीद पर अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत और भारतीय ब्रांडों द्वारा डिजाइन एवं अनुसंधान



एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि योजना अवधि में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन होगा, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा करीब 60 हजार

प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह योजना पीएलआई योजना के बाद भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को और गति देने के लिए सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को भी 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी। यह कार्यक्रम चिप डिजाइन, मशीनों एवं कच्चे माल के निर्माण, नए फैब स्थापित करने, एटीएमपी/ओसैट इकाइयों के विस्तार, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास जैसे छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा।



रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने गठन के बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय गरिमा और अनुशासन की ऐसी उत्कृष्ट परंपराएं विकसित की हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि 1 नवंबर 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण किया गया था और आज उसी परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण राज्यपाल श्री रमेन डेका के करकमलों से संपन्न हुआ है। (समाचार पेज-8 पर)

प्रमुख समाचार

विदेश यात्रा के दौरान किससे मिलते हैं राहुल गांधी : भाजपा

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने बुधवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पारदर्शिता को लेकर चिंता जताते हुए उनके विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में केशवन ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी लंबी विदेश यात्राओं से ब्रेक लेकर आखिरकार भारत आने का फैसला किया है। लेकिन उनकी विदेश यात्राओं को लेकर बरती जाने वाली गोपनीयता वाकई गंभीर



चिंता का विषय है। राहुल गांधी पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने वाले व्यक्ति हैं। बीजेपी नेता ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी को अपनी विदेश यात्राओं के बारे में जनता को सफाई देनी चाहिए। केशवन ने लिखा कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इसलिए हमारे लोगों और देश को उनकी गुपचुप यात्राओं के बारे में पारदर्शिता की उम्मीद करने का अधिकार है। इन यात्राओं को लेकर बना रहस्य गंभीर संदेह और शक पैदा करता है कि वह कहाँ जा रहे थे, किससे मिल रहे थे और उनका एजेंडा क्या था?

सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर केंद्र से बात करें : थरूर

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को सोनम वांगचुक से आग्रह किया कि वे नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे अपने अनशन को खत्म करें। साथ ही, उन्होंने सरकार से बातचीत करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा कदम उठाने से कमजोरी नहीं, बल्कि राजनेताओं वाली समझदारी और परिपक्वता दिखेगी। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को लिखे एक खुले पत्र में थरूर ने कहा कि सोमवार से संसद का सत्र फिर से शुरू हो रहा है, ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर छात्रों के मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। थरूर ने कहा कि समस्या का समाधान वहीं होना चाहिए, न कि आमरण अनशन से। कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज मैं आपसे एक राजनेता या सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बात कर रहा हूँ जो युवा भारतीयों की आपकी पीढ़ी के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर बहुत परेशान है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत मामला है।



सुप्रिया सुले ने परिसीमन बिल पर पार्टी का रुख साफ किया

मुंबई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बुधवार को प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर अपनी पार्टी के रुख को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने इस विवाद को छोटी सी बात का बतंगड बताया और कहा कि एनसीपी (एसपी) ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक रुख नहीं अपनाया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार और वरिष्ठ नेताओं जयंत पाटिल व शशिकांत शिंदे के साथ चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुले ने कहा कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं जिनमें दावा किया गया है कि एनसीपी (एसपी) ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है। सुले ने कहा कि यह राई का पहाड़ बनाने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ऐसे किसी बिल पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी जो उसे अभी तक मिला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी बिल पर बात नहीं कर रही हूँ। बिल हमारे सामने नहीं है। जब यह हमें मिल जाएगा।



प्रशांत की पार्टी से चुनाव में उतरे तीन दिग्गज भाजपा में शामिल

पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका लगा है। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जनसुराज के कई प्रमुख नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष



संजय सरावगी ने सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि यह सभी संगठन की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। भाजपा में शामिल होने वालों में दीघा विधानसभा से जन सुराज के पूर्व प्रत्याशी बिदू सिंह, कुम्हार विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी के.सी. सिन्हा और मनेर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह प्रमुख हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ली। बिदू सिंह की पत्नी विनीता बिदू सिंह, जो मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया।

बंगाल की बेटी को मिलेगा इंसाफ जनता दरबार पहुंचा पीड़ित परिवार

कोलकाता। कामदुनी दुष्कर्म-हत्या पीड़िता के परिवार के सदस्य बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी के जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ दिन पहले ही राज्य के भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने 13 साल पहले हुए अपराध की फाइलों को फिर से खोलने की बात कही।



2013 की कामदुनी घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दो प्रमुख चेहरे, तुप्पा कोयल और मौसमी कोयल, मुख्यमंत्री के साथ हुई मुलाकात के दौरान पीड़ित के परिवार के सदस्यों के साथ थे। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, जनता दरबार के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों पर उचित प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर लोगों की शिकायतें सुनने और अधिकारियों को उनका तुरंत निवारण करने के निर्देश देने के लिए अपना जनता दरबार आयोजित करते आ रहे हैं। इस तरह का पहला साप्ताहिक कार्यक्रम 18 मई को आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद अधिकारी ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा था कि नागरिक हर सप्ताह उनसे सीधे मिल सकेंगे।

गाँव में उनकी महिमा का बखान, महाप्रभु विपदा-आपदा में मदद करते हैं

द्रौपदी मुर्मू

बचपन से मुझे श्रीजगन्नाथ जी की अनेक प्रार्थनाएँ और भजन याद हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ते समय मैं गीत गाया करती थी। जगन्नाथ जी का भजन गाकर मैं खुश होती थी। महाप्रभु को अपने निकट पाती थी। अब गीत नहीं गाती। किंतु साँझ-सबरे महाप्रभु का स्मरण करके उनके भजन गुगुना लेती हूँ। मुझे लगता है कि महाप्रभु हर वक्त मेरे आस-पास ही रहते हैं। विपदा-आपदा में मेरी मदद करते हैं। भक्तकवि मधुसूदन राव का गीत आज भी मैं मन ही मन गाती हूँ।

मेरे पास दिन-रात रहते हैं महाप्रभु परमेश्वर, यह बात याद कर हृदय में पुजुँगा उन्हें निरंतर। मैं कुछ समझने-बूझने की उम्र में पहुँचने तक जगन्नाथ जी को जानने लगी थी। हमारे घर में

अक्सर जगन्नाथ जी की चर्चा होती थी। गाँव के हर टोले में उनकी महिमा का बखान होता था। जब मैं गाँव के स्कूल में पढ़ती थी, भक्त सालबेग की आहें नीड़ो शोइड़ो प्रार्थना गाई जाती थी। स्कूल के शिक्षक जगन्नाथ जी के बारे में तरह-तरह की बातें कहा करते थे। पुरी में बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर और कहाँ नहीं है! मंदिर में श्रीजगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ पूजे जाते हैं। जगन्नाथ जी का रंग काला है, उनकी आँखें गोल-गोल हैं। सुभद्रा जी का रंग पीला है, बलभद्र है चौदनी फूल की तरह सफेद। वह छवि एक बार देख लेने के बाद फिर भुलाए नहीं भूलती। सर यह भी कहते थे, जगन्नाथ हैं ‘महाप्रभु’, उनका प्रसाद महाप्रसाद है, उनका मंदिर बड़ा मंदिर है, उनका पथ विशाल पथ

(बोड़ो दांडो) है, और उनका समुद्र महोदधि है। मयूरभंज के उपरबेड़ा गाँव से पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी की दूरी बहुत थी! भला देखने का अक्सर मुझे कहाँ मिलता। किंतु मैं भुवनेश्वर गई और मैंने यूनित-2 के गल्लस हाईस्कूल में नाम लिखवाया। हॉस्टल में रहने लगी। उसके बाद मैंने पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क देखा। पहली बार जगन्नाथ दर्शन की स्मृति मेरे मन से मिटी नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर, बड़े-बड़े देवाल। भला ये सब भुलाए जा सकते हैं? क्या भुलाई जा सकती है उनकी रथयात्रा? बारह महीने में तेरह पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं श्रीक्षेत्र में। लेकिन रथयात्रा की छटा तो निराली होती है। पूरे वर्ष भक्तगण यहाँ आकर महाप्रभु का दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर जाकर। किंतु वर्ष में एक बार महाप्रभु अपने भव्य मंदिर से बाहर



विशाल पथ (बोड़ो दांडो) पर आते हैं। भक्तों को दर्शन देते हैं। तीन रथ पर तीन ठाकुर बैठकर चक्रराज सुदर्शन के साथ गुंडिचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। वहाँ सात दिनों तक रहकर वापस लौट आते हैं। महाप्रभु का यह महापर्व अतुलनीय है। बचपन से मैं जगन्नाथ जी की भक्त हूँ। वे सर्वदा मेरे परम आराध्य हैं। मेरे जीवन के उत्थान और पतन के वे निर्यता हैं। मेरे दुख-सुख के कर्ता-धर्ता हैं। जीवन में मैंने बहुत कष्ट भी सहे

हैं। उन सब दारुण दुखों से उबारा है मुझे महाबाहु ने। मैं उनकी बेटी जो हूँ। राष्ट्रपति पद के लिए मुझे उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही मैंने महाप्रभु का स्मरण किया। इतनी ऊँचाई पर मुझे ले जा रहे हो प्रभु, पग-पग पर मुझे सहारा देना, सदा मेरे पास रहना - यह मेरी प्रार्थना थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी, सुन भी रहे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान रथयात्रा का महापर्व आया। परंतु पुरी जाना संभव नहीं था। रथयात्रा के दिन बड़े भोर में दिल्ली के हौजखास में बने जगन्नाथ मंदिर जाकर मैंने महाप्रभु अलुलनीय है। बचपन से मैं जगन्नाथ जी की भक्त हूँ। वे सर्वदा मेरे परम आराध्य हैं। मेरे जीवन के उत्थान और पतन के वे निर्यता हैं। मेरे दुख-सुख के कर्ता-धर्ता हैं। जीवन में मैंने बहुत कष्ट भी सहे

2022 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में शपथ लेने जाते समय मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते- करते जा रही थी। उनके आशीर्वाद से मेरा शपथ-पाठ खूब अच्छी तरह संपन्न हुआ। राष्ट्रपति के रूप में मेरे प्रथम भाषण के समय मानो वे मेरे साथ ही थे। पुरी जाकर महाप्रभु के दर्शन के लिए मेरा मन व्याकुल हो उठा। दिन बीतते चले गए, लेकिन मैं पुरी नहीं आ सकी। मुझे लगा कि बिना उनके बुलावे के कोई कैसे उनके पास जा सकता है! मैंने मन ही मन उनसे कहा, मेरा कोई दोष हो तो क्षमा करो प्रभु, मुझे पुरी बुलाओ, दर्शन दो। वे भाव के ठाकुर हैं। मेरा भाव कैसे नहीं समझते? कुछ ही दिनों में पुरी जाने का कार्यक्रम तय हो गया। उस दिन 10 नवंबर, 2022 पुरी में अवतरण करने के बाद कार-केड चल पड़ा श्रीमंदिर की ओर।

कार-केड पुरी के प्रशस्त पावन-पथ पर पहुँचते ही मेरे अंदर एक अपूर्व भावना का संचार हुआ। यह विशाल-पथ महाप्रभु जगन्नाथ का ही है। यहाँ क्या आवश्यकता है प्रोटोकॉल की? पुरी तो क्षेत्रराज के रूप में प्रसिद्ध है। महाप्रभु देवाधिदेव हैं। और अधिक कुछ सोचने से पहले मैंने गाड़ी रुकवाई। मेरी गाड़ी रुकने पर पीछे आ रही सारी गाड़ियाँ रुक गईं। किसी के कुछ समझने से पहले मैंने पावन-पथ पर कुछ पैर चलना शुरू कर दिया। श्रीमंदिर लगभग दो किलोमीटर दूर था। मंदिर के नीलचक्र और पतित पावन-ध्वज को देखते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। पथ के दोनों किनारों पर खड़े बच्चों, महिलाओं, युवा-छात्रों और बुजुर्गों को नमस्कार भी करती जा रही थी। मेरा ध्यान था जगन्नाथ जी के पास।



नेशनल हाईवे पर भीषण त्रिकोणीय सड़क हादसा

आरंग। नेशनल हाईवे 53 (एनएच-53) पर मंदिर हसीद पुलिस थाना के ठीक सामने आज एक भीषण त्रिकोणीय सड़क हादसा हुआ। तेज गति से आ रहे एक भारी कंटेनर, रायपुर जा रही यात्री बस और पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन डायल 112 के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें तीनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में किसी भी यात्री या पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस की आपातकालीन सेवा ‘डायल 112’ की टीम पलौद मोड़ की तरफ से नियमित पेट्रोलिंग पूरी कर वापस मंदिर हसीद थाने लौट रही थी। जैसे ही डायल 112 का वाहन थाने के सामने हाईवे से अंदर मुड़ने लगा, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार बड़े कंटेनर ने पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। कंटेनर

की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसी दौरान, कंटेनर के ठीक पीछे चल रही किरण ट्रेवल्स की बस (क्रमांक सीजी 06 एनएच 9519) भी अनियंत्रित होकर कंटेनर के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। डायल 112 की गाड़ी का अगला और साइड का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया है, और इंजन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं किरण बस का सामने का हिस्सा (फ्रंट बंपर और विंडशील्ड) बुरी तरह टूट गया। हादसे के वक्त बस में यात्री सवार थे, जिससे अचानक हुए झटके के कारण बस के भीतर कुछ समय के लिए चीख-पुकार मच गई। वहीं कंटेनर का पिछला दरवाजा और बाँड़ी भी इस टक्कर में क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

सरकारी दफ्तरों के 2 साल तक काटे चक्कर

मुंगेली। पूरी जिंदगी ईमानदारी से स्कूल प्राचार्य के रूप में सेवा देने वाले सेवानिवृत्त प्राचार्य राजेंद्र कुमार अंचल आज अपने ही पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सेवानिवृत्ति के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक न तो पेंशन मिली है और न ही ग्रेच्युटी। लगातार विभागीय उदासीनता से परेशान, सेवानिवृत्त प्राचार्य ने जल्द न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है। राजेंद्र कुमार अंचल ने दस्तावेजों के साथ लछुराम डॉट काम से अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि वे 30 अप्रैल 2024 को बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, करमा से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद से वे पेंशन और

ग्रेच्युटी के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनका वैधानिक लाभ नहीं मिल सका है। पीडित रिटायर्ड प्राचार्य अंचल का कहना है कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, लोक शिक्षण संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षा सचिव कमलप्रती सिंह और शिक्षा मंत्री को ओएसडी राहुल सिंह तक अपनी शिकायत पहुंवाई, लेकिन कहीं से भी समाधान नहीं मिला। शैक्षिकसंसाधन पीडित प्राचार्य के मुताबिक, विभागीय अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि लोक आयोग में लंबित शिकायत के कारण उनकी पेंशन प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके बाद उन्होंने लोक आयोग में अपना पक्ष रखकर मामले का निराकरण भी करा लिया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी विभाग ने पेंशन संबंधी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई।

डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई

मौके पर ही टिफिन आईईडी और पाइप बम निष्क्रिय

कांकेर। कांकेर नारायणपुर सीमा से लगे जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में छिपाए गए नक्सली डंप से हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई। बरामद टिफिन ढुबध्र, पाइप बम और बीजीएल सेल को बीडीएस टीम ने मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया। कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के अनुसार जिले के नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बुधवार को डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के हेतारकसा, पल्लहूर और जपमरका गांवों के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान एक नक्सल डंप का पता लगाया। सुरक्षा बलों ने डंप से



एक 1303 रायफल मैगजीन सहित, एक बीजीएल लॉन्चर, 1303 रायफल के 4 राउंड, एक-47 के 30 राउंड, एसएलआर के 4 राउंड, 10 बीजीएल सेल, करीब 3 किलो का एक टिफिन ढुबध्र, दो पाइप बम सहित अन्य नक्सली सामग्री बरामद की। बरामद विस्फोटकों को सुरक्षा के मद्देनजर बीडीएस टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व बीएसएफ, डीआरजी और कोयलीबेड़ा थाना पुलिस के अधिकारियों ने किया। पुलिस का यह भी कहना है कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए डीआरजी, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्चिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

3 कारों से पकड़ा 552 किलो गांजा, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

जशपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई में तीन कारों से कुल 552.10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करों को पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए रेकी कर रही एक कार को भी जब्त किया गया है।

यह विशेष अभियान पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के नेतृत्व में पूरे सरगुजा संभाग में चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य मादक



पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना और नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इसके लिए संभाग के सभी जिलों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर लगातार संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जशपुर

पुलिस ने थाना कुनकुरी और थाना बगीचा क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से अवैध गांजा की खेप लेकर जा रहे इनोवा, ब्रेजा और आर्टिगा कारों को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी के दौरान वाहनों से 550 किलोग्राम से अधिक गांजा

कांग्रे घाटी में 250 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया, 70 ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर दफ्तर

जगदलपुर। वन विभाग ने करीब 250 एकड़ जमीन को अतिक्रमण बताते हुए ग्रामीणों को खेती करने से रोक दिया। इससे नाराज करीब 70 ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का दावा है कि वे पिछले 60 वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उनके पास वन अधिकार पत्र नहीं होने के कारण उन्हें खेती से वंचित किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने मामले में डीएफओ से चर्चा कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामीण जयदेव नाग ने बताया कि वन विभाग की इस कार्रवाई से नाराज करीब 70 ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण का कहना है कि उनके परिवार कई पीढ़ियों से, करीब 60 वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। खेती करने के लिए मना कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कहा है कि वो संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करेंगे। हम 60 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। हमारी गुड़ी भी उसी जमीन पर है। हमारे देवी देवता हैं। हमारा वन अधिकार पट्टा नहीं बनाया गया है। हमें पट्टा दिखाने कहा जा रहा है। जब पट्टा बना ही नहीं है तो कैसे दिखाएं-जयदेव नाग,ग्रामीण आज तक



वन अधिकार पत्र नहीं मिला। लंबे समय से इस भूमि पर निर्भर हैं। यही नहीं इस भूमि पर ग्रामीणों के देवी देवता का भी पूजा पाठ किया जाता है। प्रशासन से खेती जारी रखने की अनुमति और वन अधिकार संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरे मामले में वन विभाग की डीएफओ से चर्चा कर तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कांग्रे वैली राष्ट्रीय उद्यान के रखर कमल तिवारी ने कहा कि चितलगुर गांव में वन विभाग ने करीब 250 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। संबंधित जमीन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आती है और बिना वैध दस्तावेज के खेती करना नियमों के विरुद्ध है।

क्रमोन्जति वेतनमान मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की रिट याचिकाएं



बिलासपुर। क्रमोन्जति वेतनमान के मामले में धमतरी जिले के 14 शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने शिक्षकों की रिट याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर डिवीजन बेंच पहले ही स्पष्ट फैसला दे चुकी है। ऐसे में उसी निर्णय के अनुरूप वर्तमान याचिकाओं में अलग राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। बता दें कि धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड में पदस्थ शिक्षक भुवन लाल बैस, संजय कुमार साहू, मितेश कुमार पाल, लीला राम साहू, लक्ष्मी साहू सहित अन्य सहायक शिक्षक और व्याख्याता (एलबी) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के तहत क्रमोजति वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विभाग द्वारा लाभ देने से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख

किया था। सिंगल बेंच ने कहा कि सभी याचिकाओं में कानून और तथ्यों का प्रश्न समान है, इसलिए सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर एक ही आदेश पारित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि यही विवाद पहले स्मृति आभा नामदेव और अन्य बनाम राज्य शासन प्रकरण में तय किया जा चुका है। उस मामले में हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2026 को पुष्पलता माणिकपुरी एवं अन्य बनाम राज्य शासन के निर्णय का अनुसरण करते हुए स्पष्ट किया था कि संबंधित कर्मचारी स्मृति सोना साहू प्रकरण के समान परिस्थितियों में नहीं आते, इसलिए उन्हें 10 मार्च 2017 के परिपत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि जब डिवीजन बेंच इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय दे चुकी है, उसी के अनुरूप वर्तमान सभी याचिकाओं का निराकरण किया जाना उचित है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

तीन चोर पकड़े, लूट की केबल तार जल्द; चार अभी फरार

कोरबा। एसईसीएल गेवरा माईस के बैंकअप ऑफिस में हुई लूटपाट के मामले में दीपका पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर ऑफिस में घुसकर कर्मचारी और सीआईएसएफ जवान से मारपीट की थी। उन्होंने मोबाइल फोन और कीमती केबल तार लूट लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। यह घटना 7 जुलाई की रात करीब 11 बजे हुई थी। 10 से 12 नकाबपोश बदमाश गेवरा माईस के बैंकअप ऑफिस में घुसे थे। वहां ड्यूटी पर तैनात एसईसीएल कर्मचारी जगन्नाथ पटेल से उनका मोबाइल छीन लिया। कार्यालय में रखा कीमती तांबे का केबल वायर भी लूट लिया। वारदात के दौरान सीआईएसएफ जवान मिथुन एम ने विरोध किया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और उनका सैमसंग एस-22 मोबाइल भी लूटकर फरार हो गए। घटना की शिकायत पर थाना दीपका में अपराध क्रमांक 317/2026, धारा 310(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया ।

तीरथगढ़ वाटरफॉल पर सैलानियों से गाली-गलौज व मारपीट

जगदलपुर। शहर से 40 किमी दूर स्थित तीरथगढ़ वाटरफॉल में नहा रहे युवकों को कुछ लोगों के द्वारा डंडे से मारने के साथ ही गाली गलौज भी दिया जा रहा है। फिलहाल किस कारण से युवकों के साथ मारपीट किया गया है। इसकी जानकारी अब तक नहीं लगी है, लेकिन इसका वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है। मामले की जानकारी लगते ही जांच भी शुरू कर दी गई है। तीरथगढ़ जिलाप्रताप को देखने के लिए आ सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों की भीड़ आती है। इस 50 फीट ऊंचे वाटरफॉल की खूबसूरती सफेद बहते पानी लोगों को अपनी खूबसूरती की ओर आकर्षित करती है। दो दिन पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। जिसमें कुछ युवा नीचे से ऊपर पथरों पर चढ़कर नहा रहे थे कि अचानक से कुछ लोग हाथों में डंडा लेकर आकर वहां पर नहा रहे युवकों के साथ गाली गलौज करने के साथ ही डंडे से मारपीट करने लगते हैं। वहां मौजूद कुछ युवकों ने इस मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

सीमेंट प्लांट के खिलाफ गांवों का आक्रोश, 21 जुलाई आंदोलन

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के आरसमेटा ग्राम पंचायत में स्थापित सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है। प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ क्षेत्र की जनता काफी आक्रोशित है। क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों ने एकजुट होकर 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। चारों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट किसी भी तरह की सुविधाएं गांवों को उपलब्ध नहीं करा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम आरसमेटा,परसदा,अमोरा,सोनसरी पंचायतों में से किसी में भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। साल भर में सीएसआर के नाम पर जो पैसे दिए गए उनसे गांवों का कोई विकास नहीं हुआ। प्लांट के प्रभावित गांव के जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अपने समस्या को कई बार शासन प्रशासन और प्लांट प्रबंधन को बताया। इसके बाद जिला प्रशासन ने दखल देते हुए ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच समझौता करवाया।इसके बाद भी गांवों की हालत नहीं बदली।

कौशल विकास ट्रेनिंग से बदल रहा युवाओं का जीवन

सरगुजा। बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए शासन की कुछ योजनाएं नई राह खोल सकती हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवक स्किलड होकर प्लेसमेंट में नौकरी या स्वरोजगार से भी आमदनी कमा सकते हैं। सरगुजा जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। युवा कौशल दिवस पर हम सरगुजा के ऐसे युवाओं की कहानी लेकर आये हैं, जिन्होंने इस योजना से रिकल हासिल की किरण बताती हैं कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान में ब्यूटीशियन का कोर्स किया और आज अपना खुद का पार्लर चला रही हैं। 50 हजार का पर्सनल लोन लेकर इस महिला ने अपने घर पर ही पार्लर शुरू किया और आज 30 हजार से 50 हजार तक महीने की आमदनी कर रही हैं। एक छात्रा प्रियंका विश्वकर्मा ने लाइवलीहुड कॉलेज से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण लिया और आज ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख कर एक डिजायनर के यहां काम पर लग चुकी हैं।

आजादी के बाद भी कुदरापा में नहीं खुला प्राथमिक स्कूल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। आजादी के दशकों बाद भी एमसीबी जिले के भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ वनांचल स्थित ग्राम कुदरापा में प्राथमिक स्कूल नहीं है। छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबी दूरी और सुरक्षा की चिंता के कारण कई बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। वर्षों से स्कूल और उपस्वास्थ्य केंद्र की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पेलर नहीं हुई। इतनी कम उम्र में बच्चों को 20-25 किलोमीटर दूर स्कूल भेजने से परिजनों को चिंता होती है। गांव में प्राथमिक स्कूल खुलेगा तो बच्चे सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। गांव के राजेश ने बताया कि पिछले 15 से 20 वर्षों से ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार आवेदन देते आ रहे हैं। वे खुद लिखना नहीं जानते, इसलिए दूसरों से आवेदन लिखवाकर कलेक्टर शिविर, जनसमस्या निवारण शिविर और विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में जमा कराते रहे हैं।

दक्षिण बस्तर के माओवादी आंदोलन के गढ़ में पापा राव और उसका वर्चस्व

भावना अरोड़ा

सालों तक, दक्षिण बस्तर के जंगलों में रहने वाले ग्रामीण उसका नाम लेने से कतराते थे। माओवादी आंदोलन के इस गढ़ में, पापा राव उसके वर्चस्व का प्रतीक था। किसी गांव में उसकी मौजूदगी यह तय कर सकती थी कि किससे पूछताछ की जाएगी, किसे सजा दी जाएगी और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, कौन पुलिस का मुखबिर होने के लगातार संदेह के साए में जिएगा। डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि, आज वह डर अपनी वफादारी बदल चुका है। पापा राव को अब सुरक्षा बलों द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं है। इसकी बजाय, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर है, जिससे उसने सालों तक लड़ाई लड़ी थी। यह बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि अतीत मिट

गया है, बल्कि इसलिए है, क्योंकि उस अतीत के परिणाम अपरिहार्य हो गए हैं। जो ग्रामीण कभी माओवादी प्रभाव में रहते थे, उन्होंने उसे माफ नहीं किया। पंचायत सदस्य भूमिगत आंदोलन के दौरान उसके वर्षों से जुड़ी हिंसा को लेकर गहरा आक्रोश रखते हैं। सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि बिना सुरक्षा के, उसकी जान को खतरा पुलिस से नहीं, बल्कि उन लोगों से होगा, जिन्हें लगाता है कि कभी न्याय नहीं मिला। उनका कहना है कि पीड़ितों में से कई सामान्य ग्रामीण थे, जिन पर पुलिस मुखबिर होने का झूठा आरोप लगाया गया था। कुछ तो किशोर थे। इसके जवाब में, प्रशासन ने एक असामान्य रुख अपनाया है।

अधिकारियों ने ग्रामीण नेताओं से संपर्क किया और उनसे बदला न लेने का आग्रह किया है। उनका संदेश सीधा है-एक बार जब कोई विद्रोही औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर



देता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। कोई इस नीति से सहमत हो या नहीं, यह पुनर्वास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाता है कि हथियार डालने वालों से किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए, यदि दूसरों से भी ऐसा ही करने की उम्मीद की जाती है। माओवादी संगठन के रैंकों में पापा राव का उभार लगातार प्रगति के

साथ हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एरिया कमेट्री सदस्य के रूप में की और बाद में 2025 में दक्षिण उप-जोनल कमांडर के पद पर पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियां उन पर वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) और सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ कई हमलों में बड़ी भूमिका निभाने का आरोप लगाती हैं। इन अभियानों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 100 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। हालांकि, 2026 की शुरुआत तक, जिस संगठन को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वह अभूतपूर्व तनाव का सामना कर रहा था। महीनों तक चले लगातार उग्रवाद-विरोधी अभियानों ने माओवादी संरचनाओं के लिए उपलब्ध परिचालन क्षेत्र को काफी कम कर दिया था। वरिष्ठ नेताओं

को हत्या, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण सहित विभिन्न तरीकों से समाप्त किया जा रहा था। इकाइयों के बीच संचार तेजी से कठिन होता जा रहा था और रैंकों में अनिश्चितता फैल गई थी। जिस आत्मविश्वास ने कभी आंदोलन को जीवित रखा था, उसने इसके दीर्घकालिक अस्तित्व को लेकर संदेहों को जन्म दे दिया था। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, पापा राव और 18 अन्य माओवादियों ने 24 मार्च, 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा अधिकारी इस घटना को हाल के वर्षों में उग्रवाद के लिए सबसे बड़े झटकों में से एक मानते हैं। अपने तत्काल प्रभाव से परे, इसने माओवादी रैंकों को यह संदेश दिया कि अनुभवी कमांडर भी अब आश्चस्त नहीं थे कि आंदोलन अनिश्चित काल तक खुद को बनाए रख सकता है। बाद के महीनों में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में और अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया।

पुनर्वास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकार ने पापा राव को कड़ी निगरानी में रखा है। यद्यपि वह अपने ऊपर घोषित इनाम राशि (25 लाख रुपए) के साथ-साथ अपनी एक-47 राइफल सौंपने के लिए 3 लाख रुपए प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन ये लाभ पुनर्वास ढांचे के साथ उनके निरंतर अनुपालन पर निर्भर हैं। अधिकारी उन्हें पूरी तरह से पुनर्वासित मानने से पहले उनके आचरण की निगरानी करने का इरादा रखते हैं। यह रेखांकित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनके आत्मसमर्पण को दोषमुक्त नहीं समझा जाना चाहिए। एक आत्मसमर्पण पीड़ितों द्वारा झेली गई पीड़ा या अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दर्द को मिटा नहीं सकता। इसके अलावा, यह भूमिगत रहने के दौरान उनके कार्यकाल में की गई डूझसा के आरोपों को भी खारिज नहीं करता।

मोदी के नेतृत्व में हरियाणा बना आधुनिक रेल क्रांति का अग्रदूत

नायब सिंह सैनी

भारत आज विकास के ऐसे स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है, जहां आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्राप्ति की है। रेलवे क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। आज भारतीय रेल विश्वस्तरीय तकनीक, अत्याधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी विकास यात्रा में हरियाणा को एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का संचालन हरियाणा के जींद-सोनीपत रेलखंड पर किया जाना केवल प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। यह परियोजना विकसित भारत और ग्रीन इंडिया के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि भारत का विकास आधुनिक तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भरता पर आधारित होना चाहिए। इसी सोच का परिणाम है कि आज भारत स्वदेशी तकनीक के बल पर नई-नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना भारतीय रेलवे के इतिहास में एक परिवर्तनकारी पहल है। यह परियोजना दर्शाती है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि नई तकनीकों का निर्माता और विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र बन रहा है। पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन, निर्माण और रूपांतरण के साथ तैयार यह ट्रेन भारतीय इंजीनियरों की क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जीवंत उदाहरण है। यह हाइड्रोजन ट्रेन ब्रॉड गेज पर संचालित होने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक होगी। लगभग 141 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 यात्री कोच होंगे। लगभग 2,400 किलोवाट की शक्ति क्षमता के साथ यह भारतीय रेलवे की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल होगी। इसका सफल ट्रायल पूरा हो चुका है तथा मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि भारत अत्याधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। हरियाणा के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह परियोजना प्रदेश को आधुनिक रेलवे तकनीक का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लगभग 89 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर संचालित होने वाली इस ट्रेन से न केवल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। आज हरियाणा में जो विकास दिखाई दे रहा है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को विकास की नई गति प्रदान की है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो, रेलवे अवसंरचना का आधुनिकीकरण, हवाई सेवाओं का विस्तार, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाएं हों या आधुनिक सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, हर क्षेत्र में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट विजन रहा है कि भारत का विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के प्रत्येक राज्य और क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचें। इसी सोच के अनुरूप हरियाणा में रेलवे, सड़क, ऊर्जा, उद्योग और डिजिटल अवसंरचना को अभूतपूर्व गति मिली है। प्रदेश में आधुनिक परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन यह दर्शाता है कि डबल इंजन सरकार नजहद को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे....)

इसी तरह आगे उसकी हजार वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम। (कुरान मं0 5 सि0 21 सु0 32 श्रायत 4-5) ऊपर लिखे प्रमाणों के अनुसार जबकि हजरत नूह एक स्थान में पूरे साढ़े नौ सौ वर्ष तक रहता है तो अवश्य ही उसकी आयु इससे कहीं अधिक होनी चाहिये। इसलिये मुसलमान लोग भी पुराणोंक दीर्घायुध पर नुकताचीनी करने का क्या मजाल रखते हैं ?

आयुध्व के विषय में विदेशियों की राय
पाश्तात्य पण्डितों ने एक हद तक मनुष्य का चिरजीवी बन सकना स्वीकार किया है, यथा-
"Man may not become quite immortal yet the duration of life between brith and natural death will increase without ceasing, will have no assign-able term, and may properly be e&pressed by the word indefinite, a constant approach to an unlimited e&tent without ever reaching it or an increase in the immensity of

ages to an e&tent greater than any assignable quantity.

(M. Condorcet's problem of life)

अर्थात्- मनुष्य अमर तो नहीं हो सकता परन्तु उसके जीवन के दिन स्वाभाविक मृत्यु के दिनों से बढ़ सकते हैं और फिर यह कोई नहीं कह सकता कि अमुक पुरुष की अवस्था इतने ही दिनों की होगी। धीरे धीरे अवस्था में वृद्धि होते होते सैंकड़ों वर्षों में मनुष्य ऐसा दीर्घजीवी बन सकता है कि उसकी उमर का कोई अन्दाज नहीं कर सकता।

(देश दर्शन- पृष्ठ 100 से)
आधुनिक दीर्घजीवियों का व्यौरा
(1) बरीसाल के कौनिया नामक गाँव में सुधी खां नामक एक आदमी या जिसकी उमर का यह 114 वाँ वर्ष आरम्भ है। उसके पिता का नाम चांदखां था। उसके दांत अब भी 18 हैं।। प्रातःकाल ही उठ कर वह अपने कामों में लग जाता है।

क्रमशः ...



अमेरिका-ईरान टकराव और विश्व शांति की नई चुनौती

ललित गर्ग

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद बड़ी कठिनाई से बना संघर्ष विराम अपनी निर्धारित अवधि पूरी करने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ताजा हमलों और उसके जवाब में अमेरिका की भीषण बमबारी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को युद्ध की आशंकाओं के बीच खड़ा कर दिया है। यह केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और मानवीय मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है। जिस समय विश्व को महामारी, आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना चाहिए, उस समय महाशक्तियों का युद्धोन्माद पूरी मानवता को पीछे धकेलने का कार्य कर रहा है। होर्मुज जलडगुंरूममध्य को लेकर उत्पन्न विवाद ने इस संघर्ष को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। विश्व के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो केवल तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, आपूर्ति शृंखलाएं टूटेंगी और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होगी। युद्ध की आग कभी सीमाओं में नहीं रहती, उसकी तपिश अंततः पूरी दुनिया को झुलसाती है।

इस संघर्ष का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसमें निर्दोष नागरिकों, नाविकों और आम जनजीवन को सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के घटनाक्रम में भारतीय नाविकों के प्रभावित होने और भारत के सहयोग से विकसित रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह परियोजना को नुकसान पहुंचने से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक विश्वास-तीनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमेरिका स्वयं को लोकतंत्र और विश्व



व्यवस्था का संरक्षक बताता है, लेकिन उसकी विदेश नीति लंबे समय से प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित रही है। किसी भी राष्ट्र को झुकाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हमले और राजनीतिक दबाव स्थायी समाधान नहीं हो सकते। महाशक्ति होने का अर्थ केवल सैन्य सामर्थ्य नहीं, बल्कि संयम, दूरदृष्टि और विश्व समुदाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यदि शक्ति विवेक से संचालित न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।

दूसरी ओर ईरान को भी यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को अपने रणनीतिक हितों के लिए बंधक बनाना न तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और न ही वैश्विक विश्वास के अनुकूल। किसी भी देश की सुरक्षा तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के साथ सहयोग, विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण निर्मित न करे। भय और प्रतिशोध पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था अंततः स्वयं को ही असुरक्षित बना देती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली ने इस पूरे संकट को और अधिक

ज्ञान/मीमांसा

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भ्रष्टाचार केवल रिश्तत लेने या देने तक सीमित अपराध नहीं है,बल्कि यह लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था न्याय व्यवस्था और नागरिकों के विश्वास को भीतर से खोखला करने वाली ऐसी दीमक है जो धीरे- धीरे पूरे शासन तंत्र को कमजोर कर देती है। यदि कैसर शरीर को अंदर से नष्ट करता है,तो भ्रष्टाचार राष्ट्र की संस्थाओं, नीतियों और नैतिक मूल्यों को उसी प्रकार क्षीण करता है।भारत का आम नागरिक जन्म प्रमाण पत्र से लेकर भूमि रिकॉर्ड, पुलिस, स्थानीय निकाय, कराधान, लाइसेंस, निर्माण अनुमति और अनेक सरकारी सेवाओं तक कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की पीड़ा का अनुभव करता है।कई लोग इसे चाय-पानी कहकर सामान्य मान लेते हैं, जबकि यही छोटी-छोटी रिश्ततें आगे चलकर बड़े भ्रष्टाचार की जड़ बन जाती हैं। मैं जनता के बीच यह जनजागरण करना चाहूंगा कि आज आवश्यकता केवल भ्रष्टाचार की शिकायत करने की नहीं,बल्कि उसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाने की है। अब ऐसे समय में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2026 भारत सहित पूरी दुनियाँ के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह रिपोर्ट भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है।रिपोर्ट के अनुसार भारत 39 अंकों के साथ 91वें स्थान पर है।विशेष बात यह है कि 0 अंक का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट व्यवस्था तथा 100 अंक का अर्थ अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था है, भारत में बहुत भ्रष्टाचार है लेकिन में इस रिपोर्ट को देखकर हैरान हूं कि भारत में इतनी बड़ी लेवल पर भ्रष्टाचारी है,मैंने सोचा भी नहीं था यानें अब सारी जनता समझ रही है कि,यह स्थिति भारत की प्रतिष्ठा पर आघात व विकास में बहुत बड़ी बाधा है ? यह रिपोर्ट केवल किसी देश की रैंकिंग नहीं बताती, बल्कि यह उस देश की प्रशासनिक विश्वसनीयता,निवेश वातावरण, शासन की गुणवत्ता और संस्थागत पारदर्शिता का वैश्विक संकेतक भी मानी जाती है।किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह केवल अंक या स्थान का प्रश्न नहीं,बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, निवेशकों के विश्वास और नागरिकों की उम्मीदों का भी विषय है।

साथियों बात अगर हमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को समझने की करें तो, दुनियाँ के सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सूचकांकों में से एक



है।इसे हर वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा को 0 से 100 के पैमाने पर मापती है। 0 अंक का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट व्यवस्था तथा 100 अंक का अर्थ अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था है। इस सूचकांक की विशेषता यह है कि यह किसी एक संस्था की राय पर आधारित नहीं होता, बल्कि विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ), एशियाई विकास बैंक सहित लगभग 13 स्वतंत्र वैश्विक स्रोतों और विशेषज्ञों के आकलन को समाहित करता है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जाती है।

साथियों बात कर हम वर्ष 2026 की रिपोर्ट की करें तो इसमें वैश्विक तस्वीर चिंता पैदा करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार दुनियाँ के दो-तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है,अर्थात अधिकांश देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार गंभीर चुनौती बना हुआ है। यह स्पष्ट संकेत है कि भ्रष्टाचार केवल विकासशील देशों की समस्या नहीं, बल्कि विकसित देशों के लिए भी सतत चुनौती है।हालांकि कुछ देशों ने अपने मजबूत संस्थागत ढांचे, पारदर्शी प्रशासन और कठोर जवाबदेही व्यवस्था के कारण उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।इस वर्ष भी डेनमार्क 89 अंकों के साथ सबसे स्वच्छ देशों में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे देश हैं। इन देशों की सफलता का आधार केवल कठोर कानून नहीं,बल्कि मजबूत संस्थाएं,पारदर्शी सरकारी प्रक्रियाएं,स्वतंत्र न्यायपालिका,प्रभावी मीडिया, नागरिक सहभागिता और राजनीतिक ईमानदारी है। दूसरी ओर दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में शामिल हैं, जहां राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थाएं और प्रशासनिक विफलता ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा



साथ अलग-अलग भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इन तीनों रथों को पूरी तरह लकड़ी से बेहद शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है।

नंदीदोष : भगवान जगन्नाथ का रथ, जो पीले और लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है।

तालध्वज : बाईं हाई बलभद्र जी का

रथ, जो लाल और हरे रंग का होता है।

दर्पदलन (पद्म रथ): बहन सुभद्रा का रथ, जो लाल और काले रंग के कपड़ों से सुसज्जित होता है।

मूर्तियों को रथों पर विराजमान करने के बाद भव्य यात्रा शुरू होती है। तीनों

साथियों, भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में विशेष चर्चा का विषय बनी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 39 अंकों के साथ 91वें स्थान पर है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि भारत ने डिजिटल प्रशासन,प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधार आधारित सेवाओं,सरकारी खरीद में डिजिटलीकरण तथा कई प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से कुछ सकारात्मक प्रगति अवश्य की है,किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी, प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे अब भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं।भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विदेशी निवेश आकर्षित करने, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने,डिजिटल अर्थव्यवस्था को नेतृत्व करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल आर्थिक सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। निवेशक केवल बाजार का आकार नहीं देखते, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि किसी देश में कानून का शासन कितना मजबूत है, अनुबंधों का पालन कितना प्रभावी है और भ्रष्टाचार का स्तर कितना कम है। इसलिए भ्रष्टाचार का प्रश्न सीधे आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है।

साथियों, भारत में भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं। छोटे स्तर पर सरकारी कार्यालयों में सुविधा शुल्क, भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर, पुलिस या स्थानीय प्रशासन में रिश्तत,ठेकों में अनियमितताएं, सरकारी खरीद में पक्षपात, कर चोरी के लिए मिलीभगत, लाइसेंस और परमिट में अवैध भुगतान जैसी समस्याएं आज भी व्यापक रूप से चर्चा में रहती हैं।बड़े स्तर पर राजनीतिक वित्तपोषण, सार्वजनिक परियोजनाओं में लागत वृद्धि, प्रभाव का दुरुपयोग और सत्ता तथा व्यवसाय के बीच अपारदर्शी संबंध भी चिंता का विषय हैं।एक गंभीर सामाजिक समस्या यह भी है कि भ्रष्टाचार को अनेक लोग व्यवस्था का सामान्य हिस्सा मान चुके हैं। काम जल्दी हो जाए या बिना परेशानी के काम निकल जाए जैसी मानसिकता भ्रष्टाचार कोबढ़ावा देती है। जब रिश्तत देने वाला और लेने वाला दोनों इसे सामान्य व्यवहार मान लेते हैं, तब कानून भी सीमित प्रभाव छोड़ता है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष केवल सरकारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है।

साथियों, हाल के वर्षों में भारत ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। ई-गवर्नेंस, डिजिटल

भुगतान, डायरेक्ट बेंनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी),जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस), ऑनलाइन टेंडर प्रणाली,आधार आधारित सत्यापन, आयकर और जीएसटी का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा वितरण और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन ने भ्रष्टाचार की अनेक संभावनाओं को कम किया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों तक बिना बिचौलियों के सरकारी सहायता पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।फिर भी केवल तकनीक समाधान नहीं है। यदि संस्थागत जवाबदेही कमजोर रहे, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई न हो, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठें और दोषियों को शीघ्र दंड न मिले, तो तकनीकी सुधार भी सीमित प्रभाव ही छोड़ेंगे। इसलिए तकनीक के साथ मजबूत संस्थागत सुधार अनिवार्य हैं।

साथियों, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता आज सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक तो किंतु चुनावी वित्तपोषण यदि अपारदर्शी रहेगा तो नीति निर्माण पर निजी हितों का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों की आय, चुनावी चंदे और व्यय की पारदर्शिता लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग,नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सूचना आयोग, न्यायपालिका, सतर्कता तंत्र और स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र के प्रहरी हैं। यदि ये संस्थाएं निष्पक्ष, स्वतंत्र और संसाधन- संपन्न हों तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।।सूचना का अधिकार (आरटीआई) ने भारत में पारदर्शिता बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।अनेक चोटाले, अनियमितताएं और प्रशासनिक कमियां इसी कानून के माध्यम से सामने आईं। इसलिए पारदर्शिता और सूचना तक नागरिकों को पहुंच को और मजबूत करना समय की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई नागरिक रिश्तत देने के बजाय शिकायत दर्ज कराए, डिजिटल पोर्टल का उपयोग करे, सबूत सुरक्षित रखे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करे, तो व्यवस्था पर सकारात्मक दबाव बनता है। हर शिकायत तत्काल परिणाम नहीं देती, लेकिन सामूहिक नागरिक भागीदारी व्यवस्था में परिवर्तन का आधार बनती है।

आज का इतिहास

- 1945 अमरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया।
- 1950 फुटबॉल विश्व कप के चौथे संस्करण के फाइनल में ब्राजील को हरा उरुगवे चैंपियन बना।
- 1951 द कैचर इन द राई, जो एक अमेरिकी आने वाला उपन्यास है, जो जे.डी. सालिंगर द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- 1951 एशिया का देश नेपाल, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ।
- 1965 दक्षिण वियतनामी कर्नल फाम कोक थोओ – एक अनिर्धारित कॉन्सुनिस्ट् जापूस – नौगीन खान के खिलाफ फरवरी 1965 में तख्तापलट के प्रयास के लिए अनुपस्थित में सजा सुनाए जाने के बाद नीचे शिकार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी।
- 1981 मर्दाश्श मोहमद को मलेशिया के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, एक पद जो उन्होंने 22 वर्षों तक रखा, जिससे वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति बन गए।
- 1988 पडी एश्टाउन ब्रिटेन में लिबरल डेमोक्रेट के नेता बने।
- 1990 फिलीपींस में 7.7 की तीव्रता के भूकंप में 400 लोग मारे गये।
- 1991 यूक्रेन ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया।
- 1993 ब्रिटेन की खुफिया सेवा, एमआई5 के किसी सदस्य ने फोटो खिंचा कर पहली बार औपचारिक रूप से जनता के सामने अपनी पहचान खोली।
- 1994 धूमकेतु शोमेकर-लेवी 9 के खंडों ने प्लानेट ज्यूपिटर को मारना शुरू कर दिया, जिससे पहले एक आग का गोला बन गया जो लगभग 24,000 के। के शिखर पर पहुंच गया।
- 2004 शिकागो का मिलेनियम पार्क, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा छत उद्यान, खोला गया।
- 2007 जापान के निगाटा तट पर 6.8 तीव्रता के आए भूकंप आने से आठ लोगों की जानें गईं और 800 लोग घायल हुए। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र भी ध्वस्त हो गया।
- 2008 चीन के गांसु प्रांत के सोलह शिशुओं को दागी दूध पाउडर के कारण विक्कडनी पथरों का निदान किया गया था; कुल मिलाकर 300,000 शिशुओं की मृत्यु हो गई।
- 2009 आइसलैंड की संसद यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए वोट करती है।
- 2010 अमेरिका में जन्मे मुस्लिम धर्मगुरु अनवर अल-अवलाकी को अमेरिका में ब्लैक लिस्ट में रखा गया है।
- 2011 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा चीन के पीपुल्स रिपब्लिक की एक चेतावनी के बावजूद वाशिंगटन, डी.सी. में दलाई लामा से मिलने वाले हैं।

कुरेशी की पुस्तक से उठा सवाल

नीरज कुमार दुबे

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की आने वाली पुस्तक ने देश की राजनीति में जोरदार हनचल मचा दी है। सबसे सनसनीखेज खुलासा उस घटना का है, जब वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उनसे कथित तौर पर कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह टिप्पणी उस समय सामने आई, जब कुरैशी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से शिकायत की थी कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ मंत्री और नेता चुनाव आयोग की संवैधानिक गरिमा पर लगातार चोट कर रहे हैं। कुरैशी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी पुस्तक के उस अध्याय में दर्ज किया है, जिसका शीर्षक है, वह दिन जब प्रधानमंत्री ने अकल्पनीय बात कह दी।

कुरैशी के अनुसार यह पूरा विवाद उस समय चल रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था। उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण साढ़े चार प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत

की। आयोग ने चार दिन तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सलमान खुर्शीद को फटकार लगाई। चुनाव आयोग के पास यही सबसे कड़ी कार्रवाई उपलब्ध थी। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग को घमंडी और मनमाना तक कहना शुरू कर दिया। कुरैशी लिखते हैं कि आलोचना से उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब संवैधानिक संस्था की साख पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया।

कुरैशी के अनुसार उन्होंने अपनी पीड़ा प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार हरीश खरे के सामने रखी। अगले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से तत्काल बुलावा आया। शाम को हुई मुलाकात में मनमोहन सिंह बेहद व्यथित नजर आए। कुरैशी के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर वह खुद भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी शिकायत प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि कुछ मंत्रियों के व्यवहार से थी। इसके बाद मनमोहन सिंह ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणियों की कोई जानकारी नहीं थी। यदि पहले पता होता तो वह संबंधित मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाते। उन्होंने यह



भी कहा कि आगे कभी ऐसी कोई बात हो तो सीधे उन्हें बताई जाए। कुरैशी के अनुसार मनमोहन सिंह ने चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि यदि यह संस्था कमजोर हुई तो सब कुछ कमजोर हो जाएगा। कुरैशी का दावा है कि इस मुलाकात के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी थम गई। हालांकि यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या तत्कालीन कांग्रेसी मंत्री मनमोहन सिंह को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे थे?

साथ ही पुस्तक में कुरैशी ने एक और चौंكانे वाली बात कही है। उनका कहना है कि सरकार का हाथ हमेशा लंबा होता है, जबकि विपक्ष को सहारे की जरूरत पड़ती है।

विचार

मनमोहन को आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे कांग्रेसी मंत्री?

सहयोगियों पर नियंत्रण नहीं था।

दूसरी ओर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के हमलों को पुरानी घटना के सहारे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने कहा कि चुनिंदा घटनाओं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर आज उठ रहे गंभीर सवालों को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, निर्णय लेने की व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे को लेकर उठाए जाने वाले सवाल किसी संस्था पर हमला नहीं, बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा चुनाव आयोग को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक मानती रही है और जहां जरूरी हो वहां जवाबदेही मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है।

देखा जाये तो कुरैशी की पुस्तक केवल इस एक विवाद तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने लंबे प्रशासनिक जीवन के सौ महत्वपूर्ण प्रसंग इसमें शामिल किए हैं। वह लिखते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव का पद इसलिए स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि एक मुसलमान होने के कारण उनकी योग्यता से अधिक उनके धर्म की चर्चा होगी। उनका दावा है कि बाद में एक वरिष्ठ

अधिकारी ने यह तक कह दिया था कि वहां पहले से एक मुसलमान मौजूद है। पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मादक पदार्थों के चुनावी इस्तेमाल को लेकर आग्रह किया था, लेकिन इस पर गंभीर ध्यान कई वर्ष बाद गया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं पर भी चिंता जताने, उत्तर प्रदेश चुनाव में हाथी की मूर्तियों को ढकने के फैसले का बचाव करने और दूरदर्शन में अपनी नियुक्ति के समय सुषमा स्वराज द्वारा उनका खुलकर समर्थन किए जाने जैसी कई घटनाओं की विस्तार से जिक्र किया है।

कुल मिलाकर कुरैशी की पुस्तक ने एक साथ कई पुराने राजनीतिक घाव फिर से खोल दिए हैं। कहीं मनमोहन सिंह की संवेदनशील छवि सामने आती है, कहीं कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव की कहानी दिखाई देती है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी इन खुलासों के सहारे कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करती नजर आती है। चुनाव आयोग, सत्ता, विपक्ष और संवैधानिक संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमती यह कहानी आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का नया केंद्र बनने वाली है।

मंत्री भूपेंद्र यादव के स्टाफ को हटाने का क्या है रहस्य?

हरीश गुप्ता

दिल्ली के नौकरशाही तंत्र में तबादले, फेरबदल और यहां तक कि नाटकीय इस्तीफे भी देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में जो हुआ, उसने सरकार के सबसे पुराने अधिकारियों को भी अर्चभित कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी स्टाफ के चार सदस्यों को बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के दो दिनों के भीतर हटा दिया गया।

सेवानिवृत्त और सेवारत नौकरशाहों में से कई का कहना है कि स्वर्धन भारत में उन्हें ऐसा कोई दूसरा उदाहरण याद नहीं है जासूसी या गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के मामलों को छोड़कर जब किसी मंत्री के पूरे निजी स्टाफ को रातोंरात भंग कर दिया गया हो। यही बात इस प्रकरण को इतना रोचक बनाती है।

निजी सचिव अमर सिंह, जो 2010 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और यादव के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते हैं, को राखव आयोग में बापस भेज दिया गया है और वे नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा के शैलेश कुमार सिंह को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में एक निश्चित अवधि के लिए वापस भेज दिया गया है।

अतिरिक्त निजी सचिव आयुष सनर और सहायक निजी सचिव सिद्धार्थ यादव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। सरकार ने इस कार्रवाई के पीछे के कारणों पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। सोशल मीडिया पर आंतरिक प्रतिद्वंद्विता से लेकर बड़े प्रशासनिक बदलावों तक कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है।

यदि ये सेवा समाप्ति भ्रष्टाचार या कदाचार से



जुड़ी होती, तो आमतौर पर अनुशासनात्मक या कदाचार संबंधी कार्रवाई की जाती। इसके बजाय, दो अधिकारी चुपचाप अपने मूल विभागों में लौट गए हैं, जबकि अन्य दो की सेवा समाप्त कर दी गई है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मामला कहीं अधिक संवेदनशील और गंभीर है और पर्यावरण भवन के चारों ओर गोपनीयता का एक घेरा तैयार कर दिया गया है।

अटकलें हैं कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर की गई है। चूंकि सभी मंत्री पद की नियुक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से होती हैं – चपरासी से लेकर निजी कर्मचारी तक – इसलिए बर्खास्तगी भी प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी से ही होती है। याद कीजिए 2014 में आई उन खबरों को, जिनमें कहा गया था कि मोदी का प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसी सभी नियुक्तियों पर कड़ी नजर रख रहा है। लेकिन किसी कैबिनेट मंत्री के सभी निजी कर्मचारियों को हटाना मंत्रालय में शासन की विफलता का संकेत माना जाता है। फिलहाल सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन आधिकारिक बयान से अक्सर चुप्पी कहीं अधिक बोलती है। कारण अनुमान से कहीं अधिक गंभीर हो सकता है।

सोनम वांगचुक का लंबा अनशन अब जीवन पर भारी

कतिलाल मांडोत

दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है। अनशन के सत्रहवें दिन तक पहुंचते पहुंचते उनका स्वास्थ्य चिंताजनक स्थिति में बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार उनका वजन लगभग साढ़े आठ किलोग्राम कम हो चुका है और लगातार कमजोरी बढ़ रही है। चिकित्सकीय दृष्टि से यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर मानी जाती है। लंबे समय तक भोजन से दूर रहने का असर केवल शरीर के वजन पर ही नहीं पड़ता बल्कि हृदय गुर्दे मांसपेशियों और मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता किसी राजनीतिक मांग से अधिक एक इंसान के जीवन की होनी चाहिए।

सोनम वांगचुक देश के जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिक्षा पर्यावरण और लड़ाख जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने वर्षों तक काम किया है। ऐसे व्यक्ति की आवाज लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है। लेकिन जब विरोध का तरीका स्वयं के जीवन के लिए खतरा बनने लगे तब उस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है।

अनशन भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा का एक पुराना और प्रभावी माध्यम रहा है। महात्मा गांधी से लेकर अनेक सामाजिक नेताओं ने इसका उपयोग नैतिक दबाव बनाने के लिए किया। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि जब किसी अनशनकारी का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगता है तब आंदोलन की दिशा बदलना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। किसी भी आंदोलन का उद्देश्य जीवन की रक्षा करते हुए समाज और व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है न कि स्वयं को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना जहां जीवन ही संकट में पड़ जाए। वर्तमान समय में सोनम वांगचुक के समर्थन में कई विपक्षी नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने बयान दिए हैं। उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी की गई है। दूसरी ओर सरकार पर संवेदनहीन होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप



प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यह भी दिखाई देता है कि राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से इस मुद्दे को प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है जबकि विपक्ष सरकार को घेरने का अवसर तलाश रहा है।

यही वह बिंदु है जहां सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि हर राजनीतिक बयान अकेले अनशनकारी के स्वास्थ्य की चिंता से प्रेरित है। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है और सरकार अपने स्तर पर जवाब दे रही है। लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष के बीच सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी का हो सकता है तो वह स्वयं सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य है। वास्तविकता यह है कि यदि उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ती है तो सबसे बड़ी कीमत उन्हें और उनके परिवार को चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ जाएंगे लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता का स्वास्थ्य और जीवन वापस नहीं लौटाया जा सकता। इसलिए यह समय भावनात्मक निर्णयों से अधिक व्यावहारिक सोच का है। लंबे समय तक धूँखे रहने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कम होती है। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रक्तचाप और शुगर का संतुलन बिगड़ सकता है। हृदय की धड़कन पर भी असर पड़ सकता है। यदि समय रहते चिकित्सा और पोषण नहीं मिले तो स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए डॉक्टर भी आमतौर पर लंबे आमरण अनशन को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण मानते हैं।

सोनम वांगचुक यदि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखना चाहते हैं तो उसके अनेक लोकतांत्रिक विकल्प उपलब्ध हैं। जनसभाएं की जा सकती हैं।

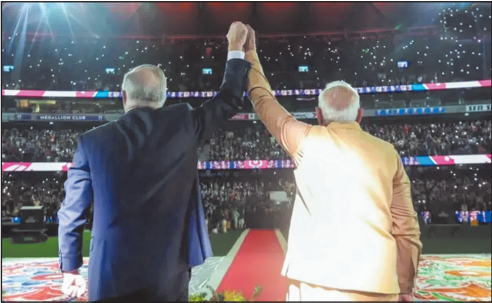
देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाया जा सकता है। अदालत का दरवाजा खटखटया जा सकता है। विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित किया जा सकता है। संसद सदस्यों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन जुटाया जा सकता है। मीडिया और सामाजिक मंचों के माध्यम से भी व्यापक जनमत तैयार किया जा सकता है। इन सभी तरीकों से आंदोलन जीवित रहेगा और नेतृत्व भी सुरक्षित रहेगा।

इस पूरे मामले में यदि कॉकरोच जनता पार्टी और आंदोलन से जुड़े अन्य लोग वास्तव में वांगचुक के शुभचिंतक हैं तो उन्हें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आंदोलन का चेहरा ही गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो आंदोलन की दिशा भी प्रभावित होती है। इसलिए पार्टी और सहयोगियों को उन्हें सम्मानपूर्वक अनशन समाप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए और संघर्ष की नई रणनीति बनानी चाहिए।

सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद हमेशा टकराव से बेहतर विकल्प होता है। यदि किसी मुद्दे पर व्यापक असंतोष दिखाई दे रहा है तो सरकार को बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। इससे तनाव कम होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की है। किसी भी विचारधारा से मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सोनम वांगचुक का संघर्ष अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन उनका जीवन उससे कहीं अधिक मूल्यवान है।

इसलिए समय की मांग यही है कि सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन समाप्त करें और लोकतांत्रिक संघर्ष का कोई दूसरा प्रभावी मार्ग चुनें। इससे उनकी बात भी मजबूत होगी और उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। आंदोलन तभी सफल माना जाएगा जब उसका नेतृत्व स्वस्थ रहकर समाज के लिए आगे भी काम करता रहे। जीवन रहेगा तभी संघर्ष भी जारी रहेगा और बदलाव की संभावना भी बनी रहेगी।



कोशिश है, जिसे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्थित रूप से नहीं साधा।

नरेंद्र मोदी की यह कूटनीतिक यात्रा ह्यूस्टन के ‘हाउडी मोदी’ से मेलबर्न के खचाखच भरे उस डॉकलैंड्स स्टेडियम तक अनवरत जारी रही, जहां उन्होंने कहा कि भजन, क्लबिंग और बैकयार्ड क्रिकेट से भरे उनके सप्ताहांत दिखाते हैं कि विदेश में जीवन और भारतीय पहचान साथ-साथ चल सकते हैं। इस भूगोल के साथ वस्तुतः एक अधिक व्यक्तिगत भाषा भी जुड़ी है, जो पारंपरिक कूटनीति के औपचारिक बयान और सीमित हाथ मिलाते से बिल्कुल अलग है। बराक ओबामा से लेकर इमैनुएल मैक्रों तक विदेशी नेताओं को दिया गया ‘मोदी हग’ अब इतना जानने-पहचानने योग्य हो गया है कि विदेशी मीडिया इसे एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में पहले से ही देखता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के साथ अपनी दो दशक पुरानी तस्वीर दिखाना, जो नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय की थी, इसी शैली को परिभाषित करता है।

संख्याएं भी मोदी की इस अनूठी कूटनीतिक शैली का हिस्सा बन चुकी हैं। उदाहरण के लिए, जकार्ता में मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को 2+6=8 को तरह पढ़ा जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांयो को उपलब्धियों से जोड़ने की कोशिश की गयी। हालांकि यह बात पूरी तरह नहीं बैठी, क्योंकि गणतंत्र दिवस एक वार्षिक आयोजन है, न कि पिछले वर्ष की घटना, जैसा कि उनका संकेत था। विपक्ष ने इसे दिखावा बताया। लेकिन

पूनम आई. कौशिश

22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व करते हैं। 7 जून, 2026 को राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नूकद, सोना और चांदी के चढ़ावे में कथित गबन का मामला सामने आता है। उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) गठित करती है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 सदस्य इस्तीफा दे देते हैं और नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) की तलाश शुरू होती है। इस प्रकार सार्वजनिक जवाबदेही की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर भी, राजनीतिक दृष्टि से ‘चंदा चोरी’ का प्रतीकात्मक महत्व चोरी की गई राशि से कहीं अधिक है। यह भाजपा के उस राजनीतिक आख्यान को चुनौती देता है, जिसमें राम मंदिर को नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया गया था। समर्थकों और विरोधियों के बीच यह प्रश्न उठ रहा है कि यदि भगवान राम को समर्पित चढ़ावा ही सुरक्षित नहीं है, तो शासन व्यवस्था पर कितना भरोसा किया जा सकता है? ऐसे में ‘चंदा चोरी’ के आरोप केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका राजनीतिक महत्व कहीं अधिक व्यापक है।उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह भाजपा के लिए सबसे गंभीर प्रतीकात्मक मुद्दा बन सकता है। यह विवाद सीधे भाजपा की सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि की नैतिक विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। यदि समय रहते इसे निर्णयित नहीं किया गया, तो इसका असर न केवल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। देश के 14 प्रधानमंत्रियों में से 8 इसी राज्य से रहे हैं यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर पड़ती है तो इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक रूप से विपक्ष ने इस मुद्दे को अपने अभियान का प्रमुख हथियार बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ‘चंदा चोरी’ को भाजपा की सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि को राजनीतिक बोझ में बदलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि, यह मतदान के रक्षान को कितना प्रभावित करेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। यदि विपक्ष इस मुद्दे को बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक, महंगाई और सत्ता-विरोधी माहौल जैसे मुद्दों से जोड़ने में सफल रहता है, तो इसका समग्र राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष

चंदा चोरी: भाजपा पर नैतिक जवाबदेही का बोझ

अखिलेश यादव पहले ही ‘चंदा चोरी’ को अपने चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा बना चुके हैं। उनका आरोप है, ‘मंदिर तो आपने बनवाया, लेकिन श्रद्धालुओं का चढ़ावा भी चुरा लिया। उसे तत्काल वापस किया जाए।’ यह आरोप भाजपा के लिए सहजता से खारिज करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे बहस धार्मिक आस्था से हटकर ईमानदारी और नैतिकता पर केंद्रित हो जाती है। इससे समाजवादी पार्टी को हिंदू मतदाताओं तक पहुंचाने का अवसर भी मिलता है। उधर भाजपा का तर्क है कि राम मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है। यदि किसी व्यक्ति ने आपराधिक कृत्य किया है, तो उसके लिए पूरी पार्टी को जिम्मेदार नहीं उहराया जा सकता। पार्टी का कहना है कि दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ट्रस्ट के नेतृत्व में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना का इस्तेमाल कर पवित्र धार्मिक परियोजना को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, यदि यह मामला चुनावी मुद्दा बनता भी है, तब भी इसके भाजपा पर व्यापक राजनीतिक प्रभाव की संभावना सीमित दिखाई देती है। अधिकांश श्रद्धहर्दू मतदाताओं के लिए राम मंदिर का निर्माण दशकों पुराने वादे की पूर्ति है। ऐसे में केवल चोरी के आरोप उस भावनात्मक जुड़ाव को कमजोर करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। भारत में मतदान का व्यवहार अनेक कारकों से प्रभावित होता है-नेतृत्व, कल्याणकारी योजनाएं, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, रोजगार, कानून-व्यवस्था, स्थानीय प्रत्यक्षी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता। कोई एक विवाद तभी निर्णायक बनता है, जब वह व्यापक जनधारणा का हिस्सा बन जाए। भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि पाखंड की धारणा बनाना हो सकती है। मतदाता अक्सर विभिन्न दलों में भ्रष्टाचार के आरोपों को सहन कर लेते हैं, लेकिन वे उन नेताओं को आसानी से माफ नहीं करते, जो स्वयं जिन नैतिक मूल्यों का प्रचार करते हैं, उन पर खरे नहीं उतरते। यदि लोगों को यह आभास होता है कि अनियमितताओं पर पर्दा डाला जा रहा है, तो उनके मन में यह धारणा बन सकती है कि भाजपा भी अन्य दलों से अलग नहीं है। अब देखना यह होगा कि घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा इस विवाद को कितनी प्रभावी ढंग से शुरुआती चरण में ही नियंत्रित कर पाते हैं।

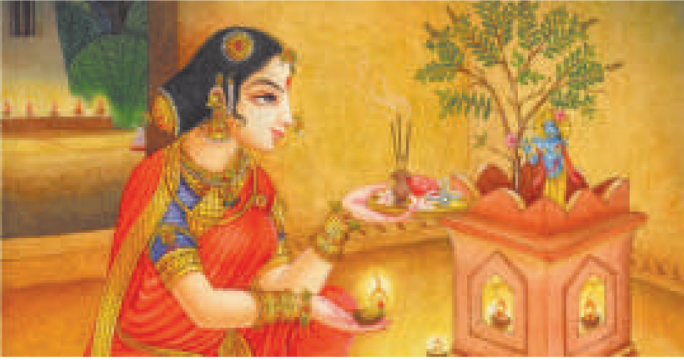
संकष्टी चतुर्थी पर कौन करता है निर्जल व्रत और क्यों



गणेश चतुर्थी कहलाती है पर संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। इस दिन धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्रियां व्रत व गणेश पूजन करती हैं। इस दिन विद्या-बुद्धि-वारिधि, संकट हरण गणेशजी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है।

पूजन किया जाता है। यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला तथा प्राणी मात्र की सभी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन कच्चे तिल को कूटकर गणेशजी की मूर्त बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद लोटे में भरा जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं भोजन करती हैं। संकट चौथ के दिन तिल को भूनकर गुड के साथ कूटकर तिलकुटा यानि तिलकुट का पहाड बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा

घर में अवश्य लगाएं तुलसी के पौधे क्योंकि



तुलसी एक ऐसा पौधा है। जिसके लाभ अनेकानेक हैं और इसे विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी के कई प्रकार हैं जैसे रक्त तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी, मुख्यरूप से विद्यमान है। तुलसी की इन सभी प्रजातियों के गुण अलग है। इन्हीं में से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपने घर का वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हैं।

- वास्तुदोष दूर करने के लिए इसे दक्षिण-पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक किसी भी खाली कोने में लगाया जा सकता है।
- तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी सामंजस्य बढ़ता है।
- पूर्व दिशा में यदि खिडकी के पास तुलसी का पौधा रखा जाए तो आपकी संतान आपका कहना मानने लगेगी।
- अगर संतान बहुत ज्यादा जिदी और अपनी मर्यादा से बाहर है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के तीन पत्ते रोज उसे किसी ना किसी तरह खिला दें।
- यदि आपकी कन्या का विवाह

तुलसी एक ऐसा पौधा है। जिसके लाभ अनेकानेक हैं और इसे विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी के कई प्रकार हैं जैसे रक्त तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी, मुख्यरूप से विद्यमान।

नहीं हो रहा हो तो तुलसी के पौधे को दक्षिण-पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से जल अर्पण करें। इस उपाय से जल्द ही योग्य वर की प्राप्ति होगी।

- यदि आपका कारीबार ठीक से नहीं चल रहा है तो तुलसी के पौधे को नैऋत्य कोण में रखकर हर शुक्रवार को कच्चा दूध चढ़ाएं।
- नौकरी में यदि उच्चाधिकारी की वजह से परेशानी हो तो ऑफिस में जहां भी खाली जगह हो वहां पर

सोमवार को तुलसी के सोलह बीज किसी सफेद कपडे में बांधकर कोने में दबा दे। इससे आपके संबंध सुधरने लगेंगे।

- शरीर में नाक, कान वायु, कफ, ज्वर खांसी और दिल की बीमारियों पर तुलसी के पत्ते रोग दूर करने में सहायक हैं।
- तुलसी एकमात्र पौधा है जो जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम है।

कर्म का आधार है विचार



विचारों से ही कर्म का जन्म होता है। वे कर्म की नींव हैं। हमारे विचार जितने अच्छे होंगे, उतने ही श्रेष्ठ हमारे कर्म भी होंगे। आचार्य शिवेंद्र नागर का चिंतन विचारों से ही कर्म का जन्म होता है। वे कर्म की नींव हैं। हमारे विचार जितने अच्छे होंगे, उतने ही श्रेष्ठ हमारे कर्म भी होंगे।

आचार्य शिवेंद्र नागर का चिंतन... वेदांत में बताया गया है कि शारीरिक कर्म मात्र परिणाम है, उसका वास्तविक कारण कुछ और है। शारीरिक कर्म होते हुए दिखता तो है, परंतु वह क्यों किया गया, इसके कारण का पता नहीं चलता। अगर मात्र शरीर ही कर्म कर रहा होता तो देहांत के बाद शरीर

कर्म क्यों करता। मृत्यु के उपरांत शरीर में कर्म करने की क्षमता कुछ देर तक रहती है। मृत व्यक्ति के अंगों का दान करने से वे जीवित व्यक्ति के लिए काम आ जाते हैं। यानी देह में मृत्यु के बाद भी कर्म करने की क्षमता होती है। कार्य करने की प्रक्रिया भले ही शरीर से होती है, लेकिन उसके अन्य कारण हैं। कर्म का कारण इच्छा है। इच्छा का कारण विचार है तथा विचार का कारण वासना है। वासना का अर्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता। वासना का एक अर्थ 'खुशबू' भी है। स्वभाव या प्रवृत्ति को भी वासना कहा गया है। वासनाएं पहले विचार रूप में प्रकट होती हैं। विचार पर केंद्रित होने पर विचार इच्छा में बदल जाता है। फिर इच्छा कर्म के रूप में प्रकट हो जाती है। आदि शंकराचार्य ने वासनाओं को 'अज्ञान' कहा है। इसीलिए योगी-महात्माओं ने विचारों की शुद्धता पर बल दिया। विचार अच्छे होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए, अगर आटे में कंकड़ हैं, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना क्यों न पकाते हों, रोटी खराब ही बनेगी। आटा अच्छा हो, तो रोटी अच्छी भी बन सकती है और खराब भी, परंतु आटा ही खराब हो तो रोटी कैसे अच्छी बनेगी। कर्म का मूल कारण विचार है, इसलिए अगर विचार नकारात्मक होंगे तो कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। कर्म अगर भवन है, तो विचार उसकी नींव। कर्म की बुनियाद ही खराब होगी तो भवन अच्छा नहीं होगा। अगर विचारों में स्थिरता है तो कार्य को करने में हमें खुशी का अनुभव होगा। आज के जीवन में तो यह और भी जरूरी है कि किसी काम की शुरुआत अच्छे विचारों से हो।

विविध

भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए पर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए ही नृसिंह अवतार लिया था। प्रहाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकशिपु का पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहाद को समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी जब प्रहाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया।

भगवान नृसिंह शक्ति के देवता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु ने 'नृसिंह अवतार' लेकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया था। भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए तथा धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों की सदैव संकट आने पर सहायता की।

नृसिंह अवतार

भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए पर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए ही नृसिंह अवतार लिया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा

ऐसा दानव जिसकी मृत्यु न तो पशु और न ही मनुष्य से हुई



इन मंत्रों का करें उच्चारण

ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्

नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्

ॐ नृम नृम नृम नर सिंहाय नमः ।

हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक शक्तिशाली मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहाद था। प्रहाद बचपन से ही भगवान विष्णु

था, वह प्रहाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखुनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया।

ऐसे करें व्रत

इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए तथा भगवान नृसिंह की विधी विधान के साथ पूजा-अर्चना करनी चाहिए।

भगवान नृसिंह तथा लक्ष्मीजी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए, तत्पश्चात वेद मंत्रों से इनकी प्राण-प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान नृसिंह की पूजा के लिए फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत व पीताम्बर रखना चाहिए। गंगाजल, काले तिल, पंच गव्य व हवन सामग्री का पूजन में उपयोग करें। भगवान नृसिंह को प्रसन्न करने के लिए उनके नृसिंह गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के पश्चात एकांत में कुश के आसन पर बैकुर रूद्राक्ष की माला से नृसिंह भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन व्रती को सामर्थ्य अनुसार तिल, स्वर्ण तथा वस्त्रादि का दान देना चाहिए। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति लौकिक दुःखों से मुक्त हो जाता है।

यह तो केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र है



प्राणों के स्पंदन से ही हमारे भीतर की सभी शक्तियां संचालित होती हैं। स्वामी विवेकानंद का चिंतन...

सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह इडा और पिंगला से ही अपना काम महाशक्ति है। मस्तिष्क द्वारा यह प्राणशक्ति विचार के रूप में प्रकट होती है। सब वस्तुएं प्राणमय हैं और यह प्राण-शक्ति ही सूर्य, चंद्र, तारे आदि इंद्रियों तक ये नाडियां आदेश पहुंचाती हैं। इडा और पिंगला का व्यवहार करना प्राणायाम का उद्देश्य है। पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। श्वासोच्छ्वास द्वारा हवा फेफड़ों में खींचना और उसके द्वारा खून साफकरना, इसमें कोई गुप्त रहस्य नहीं है। यह तो केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र है। वस्तुतः प्राणायाम से सिद्ध हुई इडा और पिंगला की गति जब नियमित होकर अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, तब हम हुई हैं, पर सुषुम्ना ज्ञानतंतुमय नहीं है।

भगीरथ ने बदायूं में किया था तप।



जेहन में कौंध जाएंगे। इसके बाद भी शायद संतोषजनक जवाब न मिल सके। इस असमंजस के जवाब को बदायूं आ

गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कहां तपस्या की थी, यह सवाल सुनकर आप भी शायद हैरत में पड़ जाएंगे। गंगोत्री से गंगासागर तक न जाने कितने तीर्थ चलचित्र की भांति आपके जेहन मे वदायूं, [लोकेश प्रताप सिंह]। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कहां तपस्या की थी, यह सवाल सुनकर आप भी शायद हैरत में पड़ जाएंगे।

गंगोत्री से गंगासागर तक न जाने कितने तीर्थ चलचित्र की भांति आपके

गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कहां तपस्या की थी, यह सवाल सुनकर आप भी शायद हैरत में पड़ जाएंगे। गंगोत्री से गंगासागर तक न जाने कितने तीर्थ चलचित्र की भांति आपके

जाएं। यहां गंगा के कछलाघाट से कुछ ही दूर पर बूढ़ी गंगा के किनारे एक

प्राचीन टीले पर अनूठी गुफा है। कपिल आश्रम के बगल स्थित इस गुफा को भगीरथ गुफा के नाम से जानते हैं। पहले यहां राजा सगर के 60 हजार पुत्रों की भी मूर्तियां थी, जो कुछ साल पहले चोरी चली गई। करीब ही राजा भगीरथ का एक अति जीर्ण-शीर्ण मंदिर है, जहां अब सिर्फ चरण पादुका बची है। आध्यात्मिक दृष्टि से सूकरखेत (बाहर क्षेत्र) का वैसे भी बहुत महत्व है। बदायूं के कछला गंगा घाट से करीब पांच कोस की दूरी पर कासगंज की ओर बढ़कर लिखा है भगीरथ गुफा। एक गांव है होडलपुर। थोड़ी दूर जंगल के बीच एक प्राचीन टीला दिखाई पड़ता है। बरगद का विशालकाय वृक्ष और अन्य पेड़ों के झुरमुटों बीच मठिया है। इसी टीले पर स्थित है कपिल मुनि आश्रम और भगीरथ गुफा। लाखोरी ईंटों से बनी एक मठिया के द्वार पर हनुमानजी की विशालकाय मूर्ति लगी है। भीतर प्रवेश करने पर एक मूर्ति और दिखाई पड़ती है, इसे स्थानीय लोग कपिल मुनि की मूर्ति बताते हैं। मूर्ति के बगल से ही सुरंगनुमा रास्ता अंदर को जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति ही एक बार में प्रवेश कर सकता है। पांच मीटर भीतर तक ही सुरंग की दीवारों पर लाखोरी ईंटें दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है कच्ची अंधेरी गुफा। सुरंगनुमा रास्ते से भीतर जाने के बाद एक बड़ी कोठरी मिलती है, जहां एक शिवलिंग भी कोने में है। कोठरी के बाद फिर सुरंग और फिर कोठरी। पर्याप्त रोशनी के साथ इस रास्ते से बढ़ते हुए चौथी कोठरी तक पहुंचने के बाद तो साथ गए स्थानीय फरीदपुर के श्याम गिरि की भी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने सुझाव दिया कि यहां तक भी कोई नहीं आता, बिना ऑक्सीजन मास्क के आगे चलना ठीक नहीं है। श्याम गिरि ने बताया

कि पहले गंगा इसी टीले के बगल से होकर बहती थीं। अभी भी गंगा की एक धारा समीप से होकर बहती है, जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। टीले के नीचे स्थित मंदिर से दुर्लभ मुखार बिंदु शिवलिंग भी चोरी चला गया था। इन घटनाओं की बाकायदा प्राथमिकी दर्ज हुई। बाद में पुलिस ने पाली (अलीगढ़) के एक तालाब से शिवलिंग तो बरामद कर लिया, लेकिन सगर पुत्रों की मूर्तियों का अभी भी कोई पता नहीं है। इसी टीले पर तीन समाधि भी हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरिदास की समाधि कहते हैं। यहां राजा भगीरथ का मंदिर है, जो कभी बहुत भव्य था।

कछला बनेगा भगीरथ नगर

बदायूं के कछला घाट पर निर्मल गंगा अभियान चला तो गंगासेवी वयोवृद्ध संत त्रिदंडी स्वामी वासुदेवाचार्य ने भगीरथ गुफा के बारे में जानकारी दी। श्री भगीरथ सेवा न्यास ने अभियान से जुड़े कई संगठनों को लेकर कछला घाट पर महाआरती की परंपरा शुरू की तो संतों-धर्माचार्यों ने कछला का नाम भगीरथ नगर करने की मांग उठाई। गौरीशंकर मंदिर के मुख्य आचार्य नारायण दास मुदगल कहते हैं कि इस समय भगीरथ गुफा से सबसे करीब कछला में ही सुविधाजनक गंगा घाट है। इसलिए यही कछला का नाम भगीरथ नगर होना चाहिए और संत-धर्माचार्य खुद यहां राजा भगीरथ का भव्य मंदिर बनवाएंगे। अखिल भारतीय संत सभा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी पगलानंद भी संतों-धर्माचार्यों के साथ बीते सप्ताह भगीरथ गुफा का दर्शन करके आए। नगर पंचायत कछला की चेयरमैन पुष्पा देवी ने बोर्ड की ओर से कछला का नाम भगीरथ नगर किए जाने का प्रस्ताव पारित करवाने का आश्वासन संतों को दिया है।

हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट

नईदिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में आतंकी संगठ लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. हाफिज सईद के खिलाफ इस आदेश के बाद ट्रायल भी शुरू हो सकता है. हाफिज सईद की गैर मौजूदगी में पहलगाम हमले को लेकर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है. इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाफिज सईद को हमले का मास्टरमाइंड बताया है. एनआईए ने हाफिज सईद के खिलाफ 60 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है. कोर्ट से जारी वारंट और हालिया घटनाक्रमों को पहलगाम हमले की जांच में बड़ा कदम माना जा रहा है. एनआईए की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है।

चारा घोटाला केस में लालू यादव को राहत

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. यह मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी थ्रष्ट की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें थ्रष्ट ने सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई जल्द पूरी करे.दरअसल, लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को चारा घोटाला मामले में साल 2018 में दोषी करार दिया गया था. लेकिन यह अपील अब तक हाईकोर्ट में लंबित है. मामले की सुनवाई पूरी न होने के चलते कोर्ट ने साल 2021 में लालू यादव को जमानत दे दी थी. उस समय कोर्ट ने कहा था कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आता, तब तक उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत होगी।

भारत ने यूएन में किया फिलिस्तीन का समर्थन

नई दिल्ली। भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है. साथ ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल संघर्ष के समाधान के लिए ‘दो-राष्ट्र समाधान’ की अपनी पुरानी नीति को दोहराया है. विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने सोमवार को ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की इस स्थिति को स्पष्ट किया. विदेश मंत्रालय के अनुसार, फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की बैठक में रंगनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है. उन्होंने %दो-राष्ट्र समाधान% और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए भारत का निरंतर समर्थन दोहराया. मंत्रालय ने बताया कि श्रीप्रिया रंगनाथन ने बैठक में भारत द्वारा फिलिस्तीन को दिए जा रहे विकास सहयोग, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और मानवीय सहायता का जिक्र किया।

भारतीयों पर हमले के बाद ईरानी राजदूत तलब

नई दिल्ली। ईरान ने सोमवार देर रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यूएई के दो तेल टैंकर एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर क़रूज मिसाइलों से हमला किया. हादसे में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों जहाजों पर कुल 46 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें 30 भारतीय शामिल थे. एमटी अल बहियाह पर मौजूद 12 भारतीयों में से एक की मौत हो गई और एक अन्य घायल है. वहीं, एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से नौ घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है. घटना के बाद भारत ने मंगलवार सुबह ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी सहित ईरानी राजनयिकों को तलब कर कड़ी चिंता जताई और मामले में जवाब मांगा. बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 13 भारतीयों की जान जा चुकी है. अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच फारस की खाड़ी में 7 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं, जिन पर 148 भारतीय नाविक सवार हैं. एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, ये जहाज तनाव बढ़ने से पहले ही होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में पहुंच चुके थे।

पीओके में रैंजर्स ने 8 को गोलियों से भूना

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मंगलवार को हालात तनावपूर्ण हो गए. मुजफ्फराबाद तक प्रस्तावित जन मार्च से पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की. इस दौरान पाकिस्तानी रैंजर्स की फायरिंग में कम से कम आठ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.रिपोर्ट्स के मुताबिक, रावलकोट बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे. इनमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी थी. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए. इसके बाद हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने लाइव राउंड फायर किए. इस दौरान सुधानोटी इलाके में भी फायरिंग हुई. बताया गया कि वहां भी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया. इससे संकेत मिलता है कि कार्रवाई केवल एक स्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि कश्मीर के कई हिस्सों में एक साथ अभियान चलाया गया. पाकिस्तानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पहले से ही सक्रिय थे।

भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा सीईटीए : मोदी

दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) आधिकारिक तौर पर लागू

नई दिल्ली/अबू धाबी। भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के आर्थिक संबंधों के लिहाज से बुधवार का दिन एक ऐतिहासिक मील का पथर है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) और सामाजिक सुरक्षा समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गए हैं। इस ऐतिहासिक कदम के तहत अब भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 99 प्रतिशत निर्यातों को जीरो-ड्यूटी (शून्य-शुल्क) के साथ बाजार पहुंच हासिल होगी, जो कुल व्यापार मूल्य का लगभग 100 प्रतिशत कवर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह साझा महत्वाकांक्षाओं को हमारे लोगों के लिए वास्तविक और ठोस अवसरों में बदलने का काम करेगा। उन्होंने रेखांकित किया कि यह क्षण दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं नवाचार द्वारा संचालित एक मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी बनाने के संकल्प को प्रदर्शित करता है। पीएम ने कहा, भारत-यूनाइटेड किंगडम साझेदारी में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है! व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) और सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने से हमारे आर्थिक संबंध और भी गहरे होने वाले हैं। ये समझौते मिलकर हमारी साझा महत्वाकांक्षा को हमारे लोगों के लिए ठोस अवसरों में तब्दील करते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि सीईटीए किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई को नई गति प्रदान करेगा, इसके अलावा कई जीवंत क्षेत्रों को यूके के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त होगी।



पीएम मोदी के अनुसार, सीईटीए हमारे किसानों, उद्यमियों और लघु व मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। कई जीवंत क्षेत्रों को यूके के बाजार में बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। यह प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार में सहयोग को भी गहरा करेगा, साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की गतिशीलता को बढ़ावा देगा। सामाजिक सुरक्षा समझौता यूके में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा। वहीं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ब्रिटिश समकक्ष पीटर काइल और दोनों देशों की वार्ताकार टीमों को इस परिवर्तनकारी समझौते को धरातल पर उतारने के लिए धन्यवाद दिया।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, यह समझौता भारत के पारंपरिक और आधुनिक दोनों क्षेत्रों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। इस समझौते (सीईटीए) के लागू होने से भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार में सीधी और मजबूत पहुंच मिलेगी।

प्रमुख निर्यात क्षेत्र : कपड़ा, चमड़ा, रब और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और विनिर्माण क्षेत्र

को इससे भारी निर्यात लाभ मिलेगा।

छोटे उद्यमियों और किसानों को सहारा: यह ऐतिहासिक समझौता देश के किसानों, उद्यमियों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नया प्रोत्साहन और गति देगा।

सेवा क्षेत्र का विस्तार : यह आईटी, वित्तीय, शिक्षा, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगा।

व्यापार सौदे के साथ-साथ लागू हुआ सामाजिक सुरक्षा समझौता भारतीय कार्यबल के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। इसके तहत-

दोहरे योगदान से मुक्ति: अस्थायी असाइनमेंट पर ब्रिटेन जाने वाले भारतीय पेशेवरों को अब पांच वर्षों तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त: वाणिज्य मंत्री गोयल ने स्पष्ट किया कि इस छूट से विदेशी जमीन पर भारतीय कंपनियों और पेशेवरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी मजबूत होगी।

प्रतिभाओं का सुगम आवागमन: यह समझौता देश के कुशल कार्यबल और विशेष रूप से तकनीकी विशेषज्ञों को ब्रिटेन में काम करने के लिए अधिक गतिशीलता और सुरक्षा प्रदान करेगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच इन दोनों समझौतों का एक साथ लागू होना वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। 99 प्रतिशत निर्यात पर शून्य-शुल्क मिलने और आईटी पेशेवरों को टैक्स में बड़ी छूट मिलने से देश में रोजगार और विदेशी निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एकूँड वित्तीय, नवाचार-संचालित और साझा समृद्धि वाली मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार तैयार करेगा।

सेंसेक्स 130 अंक चढ़ा 24,078 पर बंद हुआ निफ्टी

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बावजूद पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। हालांकि आईटी, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में कमजोरी बनी रही। बीएसई सेंसेक्स 130.49 अंक यानी 0.17 फीसदी की बढ़त के साथ 77,185.43 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 26.45 अंक यानी 0.11 फीसदी चढ़कर 24,074.85 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में आई बढ़त में अल्ट्राटेक सीमेंट और Eternal जैसे शेयरों का अहम योगदान रहा। इन शेयरों में खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांक सकारात्मक दायरे में बने रहे। बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में व्यापक बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा। निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में करीब 0.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

आईडीबीआई बैंक को मिला विदेशी खरीदार

नईदिल्ली। सरकार की लंबे समय से लंबित आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कनाडा की वित्तीय कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 5.5 अरब डॉलर (लगभग 53,000 करोड़ रुपए) की इस डील की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। यदि यह सौदा पूरा होता है, तो यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फेयरफैक्स अब 81 रुपए प्रति शेयर 75 रुपए के ऑफर से ज्यादा है। इस कीमत पर, सरकार बैंक में अपनी 45.48 फीसदी हिस्सेदारी में से 30.48% हिस्सेदारी बेचकर लगभग 26,620 करोड़ रुपए जुटा सकती है।

पहली तिमाही में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 12.74 लाख इकाई

नई दिल्ली। देश में चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 25.9 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 12,73,811 इकाई रही। उद्योग संगठन सियाम ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 10,11,884 इकाई रही थी। इससे पहले 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में रिकॉर्ड करीब 10.3 लाख इकाई की बिक्री दर्ज की गई थी। सियाम के अनुसार, पहली तिमाही में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री 20.3 प्रतिशत बढ़कर 56,28,675 इकाई रही, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 46,77,990 इकाई थी।

सिग्नेचर ग्लोबल का शुद्ध कर्ज बढ़कर 390 करोड़ रु.

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शुद्ध कर्ज बढ़कर 390 करोड़ रुपए हो गया, जो मार्च 2026 के अंत में 200 करोड़ रुपए था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, 30 जून, 2026 तक कंपनी के पास नकदी तथा बैंक में जमा राशि (सावधि जमा सहित) 2,522 करोड़ रुपए थी। इससे उसका बही-खाता मजबूत बना हुआ है और भविष्य की वृद्धि एवं परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध है। कंपनी ने साथ ही बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में बिक्री बुकिंग 25 प्रतिशत घटकर 1,970 करोड़ रुपए रह गई। इसकी मुख्य वजह बिक्री की मात्रा में कमी रही।

स्टेल प्रमुख समाचार

फीफा विश्वकप में इंग्लैंड अर्जेंटीना के बीच मुकाबला आज

अटलांटा। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में से एक फिर देखने को मिलेगी। इंग्लैंड और अर्जेंटीना 24



साल बाद विश्व कप में एक-दूसरे के खिलाफ उतरेंगे। दोनों टीमों के बीच आखिरी विश्व कप मुकाबला 2002 में खेला गया था। अब अटलांटा स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मुकाबले में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबले सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं रहे हैं। इन मैचों ने कई ऐसे पल दिए हैं, जो आज भी खेल इतिहास के सबसे यादगार घटनाक्रमों में गिने जाते हैं। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच सेमीफाइनल का प्रसारण 16 जुलाई को रात साढ़े 12 बजे से यूनाइटेड स्टोर्ट्स के चैनलों पर होगा। ओटीटी पर आप इसका लाइव प्रसारण जी5 एप पर देख सकते हैं। विश्व कप में अब तक दोनों टीमों पांच बार आमने-सामने आ चुकी हैं। यानी जीत के मामले में इंग्लैंड का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन अर्जेंटीना ने विश्व कप के सबसे अहम मौकों पर इंग्लैंड को हराकर अपनी छाप छोड़ी है। 24 साल बाद विश्व कप में दोनों टीमों फिर आमने-सामने हैं। एक ओर मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना है, जिसकी कमान लियोनल मेसी के हाथों में है।

दूसरी ओर इंग्लैंड है, जो जूड बेलिंहम और हैरी केन जैसे सितारों के दम पर 1966 के बाद पहली बार विश्व कप जीतने का सपना देख रहा है। अटलांटा में होने वाला यह मुकाबला सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं, बल्कि विश्व फुटबॉल की सबसे ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विताओं में एक नया अध्याय भी लिखेगा। अर्जेंटीना ने इस मैच के लिए नेवी ब्लू जर्सी पहनने की मांग की थी। उन्होंने विश्वकप में इंग्लैंड के खिलाफ जो दो मैच जीते हैं, जो नेवी ब्लू जर्सी में ही जीते हैं। ऐसे में अर्जेंटीना ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

शिवकांत शर्मा

भारत और ब्रिटेन के बीच बुधवार से नया मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है, जिसे व्यापक आर्थिक एवं व्यापारिक समझौता या सीटा कहा जा रहा है। इससे भारत के 99 प्रतिशत निर्यातों पर ब्रिटेन में कोई टैरिफ या शुल्क नहीं लगेगा। बदले में भारत भी ब्रितानी आयातों पर शुल्कों में 90 फीसदी की कटौती करेगा। भारत और ब्रिटेन का वस्तु व्यापार इस समय लगभग 2,510 करोड़ डॉलर है, जो 8.5 प्रतिशत सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। दोनों देश इस सीटा व्यापार समझौते की सहायता से वस्तु और सेवा व्यापार को 2030 तक 10 हजार करोड़ डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं।

इस मुक्त व्यापार समझौते से सबसे बड़ा लाभ भारत के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को होगा। मसाले, दालें, चाय, आम का गूदा, अचार, तैयार भोजन, प्रसंस्कृत

खाद्य, द्यूना और झींगा मछली जैसी चीजों से निर्यात शुल्क अब पूरी तरह हटा दिया गया है। इनमें श्रीधान्य (पांच चमत्कारी मिलेट्स), कटहल और देसी बूटियों जैसी चीजों को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे भारत के श्रमप्रधान उद्योग भी निर्यात शुल्क से छूट मिलने के कारण अब चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के माल को टक्कर देते हुए ब्रितानी बाजारों में अपनी जगह बना सकेंगे। जबकि इससे पहले भारतीय निर्यातकों को 12.5 प्रतिशत शुल्क



देना पड़ता था। चीन को छोड़कर बाकी देशों को इससे छूट थी। इसलिए ब्रिटिश सुपर बाजारों में भारतीय माल दिखाई देने लगभग बंद हो गया था। ब्रिटेन जाने वाले भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा भाग दवाओं, बिजली और उद्योगों की मशीनों, वाहनों के पुर्जों और रब-आभूषणों का होता है। इनके निर्यात पर अधिक शुल्क तो नहीं था, फिर भी उसके पूरी तरह हट जाने के बाद इन उद्योगों को चीन और यूरोप के निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा में टिकने में मदद मिल सकती है।

सच्चाई यह है कि ट्रंप की टैरिफ जंग के कारण अमेरिकी बाजार में माल बेचना कठिन

हो गया है और यूरोप के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसे में ब्रितानी समझौता इन उद्योगों के लिए नये अवसर खोलता है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सेवा व्यापार को भी बढ़ावा देगा और भारत अब एक सेवाप्रधान अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे की कंपनियों के सेवाकर्मियों से पांच साल तक समान सुरक्षा कर न वसूलने पर भी राजी हुए हैं। ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कंपनियों के सेवाकर्मियों को दोहरा कराधान कन्वेंशन के तहत पांच साल तक ब्रिटेन का राष्ट्रीय सुरक्षा कर नहीं देना होगा।

यही नियम भारत में काम करने आये ब्रिटिश कंपनियों के सेवाकर्मियों पर भी लागू होगा। ब्रिटेन में जाकर काम करने वाले अधिकांश भारतीय सेवाकर्मों सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के होते हैं, जिन्हें आयकर

के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कर भी देना होता है, जो उनके वेतन का 12.5 प्रतिशत तक होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा के क्षेत्रों में सेवा देने वाली भारतीय कंपनियों के लिए भी ब्रिटिश बाजार में प्रवेश करना अब सुगम बनेगा। दोनों देशों की कंपनियों को एक-दूसरे के यहां सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवा करने के लिए बोली लगाने का प्रावधान भी रखा गया है, जिससे आपसी निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इस समझौते को व्यापक व्यापार समझौता या सीटा कहा जा रहा है। भारत ने सेवाकर्मियों और छात्रों के आवागमन को और सुगम बनाने के लिए भी दबाव डाला था। लेकिन समझौते में सेवाकर्मियों की वीजा की संख्या बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, जो शायद ब्रिटेन में आप्रवासन विरोधी लहर को देखते हुए संभव नहीं हुआ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और स्वस्थ संसदीय परंपरा का जीवंत उदाहरण : राज्यपाल डेका

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने गठन के बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय गरिमा और अनुशासन की ऐसी उत्कृष्ट परंपराएं विकसित की हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि 1 नवंबर 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण किया गया था और आज उसी परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण राज्यपाल श्री रमेन डेका के करकमलों से संपन्न हुआ है। यह विधानसभा की संस्थागत क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में आज उत्कृष्टता अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

लोक तांत्रिक परंपराओं, संसदीय मूल्यों और उत्कृष्ट जनप्रतिनिधित्व को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित इस गरिमामयी समारोह में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक तथा अकलतरा विधायक श्री राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया।

पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए दैनिक पत्रिका के संवाददाता श्री संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए आईबीसी-24 के श्री सौरभ सिंह परिहार एवं डॉ. राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण प्रदान किया गया।

प्रदेश के विकास और जनहित के संकल्पों को साकार करने का सशक्त मंच है विधानसभा - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा लोकसेवा का वह केन्द्र है जहां जनसेवक संसदीय सदन में लोक कल्याण का पावन अनुष्ठान संपादित करते हैं और इसलिए लोकतंत्र में संसदीय सदन को मंदिर की संज्ञा दी गयी है और इस मंदिर की प्रतिष्ठा सभी सदस्यों के आचरण व्यवहार और विचार पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि



छत्तीसगढ़ विधानसभा की गणना देश की श्रेष्ठ विधानसभाओं के उदाहरण के रूप में होती है। इस विधानसभा में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य जो समन्वय है, सामन्जस्य है, और समादर का भाव है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

राज्यपाल श्री डेका ने अपने संबोधन में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए समर्पण भाव से कार्य करें। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि सभी प्रतिनिधि मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करें, तभी राज्य निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने

नकटी के लिए कांग्रेस का राजभवन मार्च, सरकार बनी तो दिलाएंगे न्याय: दीपक बैज



रायपुर। नकटी गांव के विस्थापितों के मुद्दे पर कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। नकटी से राजभवन तक निकली पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रभावित परिवारों के साथ भोजन किया। तेलीबांधा चौक पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झुमाझपटी हुई।

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक नकटी के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रभावितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

नकटी से राजभवन तक कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

नकटी गांव के विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने नकटी गांव से राजभवन तक पदयात्रा निकाली। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, विधायक, कार्यकर्ता और नकटी के प्रभावित परिवार इस पदयात्रा में शामिल हुए, यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए वीआईपी रोड पहुंची।

सड़क पर बैठकर किया भोजन, सरकार को दिया संदेश

वीआईपी रोड पर कांग्रेस ने नकटी प्रभावित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : विष्णुदेव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से ‘भावना दीदी की साईंस पाठशाला’ के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ट्यू), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (ट्यूथिंग), एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी (ऋड्युरक) जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक



प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक को मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साईंस पाठशाला’ केवल एक मोबाइल लैब नहीं, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली अभिनव पहल है। यह बच्चों में

ग्लोबल ट्रेवल एसोसिएशन अब आधिकारिक रूप से चेम्बर का नया सदस्य बना

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए यह बेहद गर्व का क्षण है कि प्रतिष्ठित ग्लोबल ट्रेवल एसोसिएशन अब आधिकारिक रूप से चेम्बर का नया सदस्य बन गया है। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी ने एसोसिएशन के नवनिर्गुक्त अध्यक्ष श्री मनीष जैन, महामंत्री श्री शुभम अग्रवाल और कोषाध्यक्ष श्री राहुल वासवानी को इस नए सफर के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री थौरानी जी के कुशल नेतृत्व में चेम्बर लगातार व्यापारियों की आवाज को शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठा रहा है और व्यापार संचालन की हर तकनीकी परेशानी को दूर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आज प्रदेश भर के व्यापारिक संघ लगातार चेम्बर से जुड़ रहे हैं। इस गरिमामयी अवसर पर सलाहकार गुणजीत सिंह संधू, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, उपाध्यक्ष -दिलीप इसरानी, मनीष प्रजापति, अमररत्न खट्टर, जितेंद्र शादीजा, मंत्री-राहुल खूबचंदानी, आकाश डुडानी सहित एसोसिएशन के सदस्यगण एवं चेम्बर पदाधिकारीगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

एचएनएलयू ने वैश्विक नवाचार और अनुसंधान के लिए 20 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ किया समझौता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर ने वैश्विक शैक्षणिक पटल पर राज्य का गौरव बढ़ाते हुए एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान, एचएनएलयू ने वैश्विक विश्वविद्यालय नवाचार एवं सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते पर दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और संयुक्त अरब अमीरातके 20 अग्रणी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम उच्च शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

बैंकॉक के आईकॉनसियाम में हुआ वैश्विक समागम

यह समझौता 9-10 जुलाई 2026 को बैंकॉक स्थित प्रसिद्ध आईकॉनसियाम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित "AAUP - WU" इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुआ। इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय सरकार के साथ साझेदारी में विश्वविद्यालय नवाचार-नीति, तंत्र और प्रभाव था, जिसमें दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के प्रमुखों, नीति-निर्माताओं, नवाचार विशेषज्ञों और जाने-माने शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया।



कुलपति प्रो. विवेकानन्दन ने प्रस्तुत किया 'R-HaS' मॉडल शिखर सम्मेलन में एचएनएलयू का प्रतिनिधित्व करते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) वी.सी. विवेकानन्दन ने विश्वविद्यालय के अभिनव रिसर्च हब एंड पोक मॉडल पर आधारित एक केस स्टडी प्रस्तुत की। इस प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने एचएनएलयू के अंतर्विषयी अनुसंधान तंत्र, बाह्य वित्तपोषित शोध परियोजनाओं तथा समाज के प्रति जवाबदेह एवं प्रभावकारी अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को वैश्विक मंच पर रेखांकित किया, जिसकी उपस्थिति विशेषज्ञों ने काफी सराहना की। इस रणनीतिक कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. विवेकानन्दन ने कहा कि एचएनएलयू क्षेत्रीय और वैश्विक विश्वविद्यालय संगठनों के साथ सार्थक सहभागिता के माध्यम से अपनी अनुसंधान पहलों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित और प्रसारित करने की दिशा में प्रभावशाली प्रगति कर रहा है। यह बहुपक्षीय समझौता हमारे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को विस्तार देने की दिशा में एक मील का पत्थर है। सम्मेलन के दौरान, ऋक महासचिव प्रो. डॉ. अनुप स्वरूप तथा कार्यकारी सचिव डॉ. सुपापोर्न चुआंगचिद के साथ संयुक्त सम्मेलन,

साय मंत्रिमंडल में अनुभवहीनता, ढाई साल में बीजेपी ने सब कुछ किया बर्बाद : उमेश पटेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने अमानक दवा से लेकर नकटी गांव के मामले पर सरकार को घेरा, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से किसी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं देने का आरोप विपक्ष ने लगाया। आखिर क्में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के जवाबों पर ऐतराज जताया, ये बताया ईटीवी भारत पर खरसिया से कांग्रेस विधायक और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि जिस दवा की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, उसकी कंपनी गुजरात में बैन है, ब्लैकलिस्टेड है. मैं दवा का नाम थोड़ा भूल रहा हूं. गुजरात में क्में बैन है, वो इसलिए बैन है क्मेंकि जो फॉर्मूला दवा में है, गुजरात सरकार ने पाया कि वो शरीर के लिए ठीक नहीं है. वो दवा को छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदकर मरीजों में बांट दिया है. हमने इस पर सवाल किया तो मंत्री जी ये मान रहे हैं कि जो फॉर्मूला आप दवा का बता रहे हैं वो सैम हैं. लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि ये अलग-अलग काम करता है. तो आप ही बताईए कि यदि कोई दवा आप लेते हैं और उनके इंफ्रिडिंट दोनों में ही समान है तो वो अलग-अलग कैसे काम करेगा. उदाहरण के लिए आप डिस्पिन यूज करते हैं और डिस्पिन में जो फॉर्मूला है वो दूसरी कंपनी इस्तेमाल करके बनाती है तो वो दवा भी सिरदर्द दूर करने का काम करेगा।



अनुसंधान परियोजनाओं, संकाय (फैकल्टी) व छात्र विनिमय (एक्सचेंज) कार्यक्रमों पर भी बेहद सार्थक चर्चा हुई है।

समझौते के तहत इन क्षेत्रों में होगा साझा काम

बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-3 के तहत सभी 20 सहभागी संस्थान भविष्य में मिलकर काम करेंगे। इसके तहत आपसी सहयोग से वैश्विक महत्व की नवाचार व शोध परियोजनाओं का संचालन, संकाय , शोधार्थियों और छात्रों के लिए विनिमय कार्यक्रम, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं और केस स्टडीज का विकास करना शामिल है।

यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक बेहद प्रतिष्ठित और पुराना विश्वविद्यालय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाकर शैक्षणिक सहयोग, नेतृत्व विकास और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन सिर्फ पारंपरिक किताबी या शोध मानकों पर नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक प्रभाव, उद्योग सहयोग, उद्यमिता और नैतिक नेतृत्व जैसे नवाचारों के आधार पर करती है। एचएनएलयू अपने दूरदर्शी नेतृत्व के कारण इस रैंकिंग में लगातार अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा है।

निलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने।
बलभद्र सुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः॥

महाप्रभु श्री
जगन्नाथ
स्थयात्रा

की प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हमसे जुड़ने
के लिए
QR स्कैन करें

छत्तीसगढ़
सहस्र ज्ञान संपत्ति | Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in